

RAJYA SABHA

Friday, the 21th April, 1962/the 1th
Vaisakha, 1884 (Saka)

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ANNOUNCEMENT *RE* GOVERN- MENT BUSINESS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA):
With your permission, Sir, I rise to announce
that during the week commencing 30th April,
1962 this House will discuss the Motion of
Thanks to the President to be moved by Prof.
R. D. Sinha Dinkar.

RESOLUTION *RE* REINSTATEMENT OF CENTRAL GOVERNMENT EM- PLOYEES WHO PARTICIPATED IN THE STRIKE OF JULY, 1960

श्री ए० बी० वाजपेयी (उत्तरप्रदेश) :
सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“इस सभा की राय है कि जुलाई
१९६० में हुई केन्द्रीय सरकार के कर्म-
चारियों की हड़ताल में भाग लेने के
लिये जितने भी केन्द्रीय सरकार के कर्म-
चारों अपने पदों से निकाले गये थे, उन्हें
उन के पदों पर पुनः नियुक्त किया जाय।”

जिन परिस्थितियों में १९६० में केन्द्रीय
सरकार के कर्मचारियों को आम हड़ताल का
फैसला करना पड़ा था वे सर्वविदित
हैं। बहुतों हुई महंगाई और उसे रोकने
में शासन की विफलता, जिस के परि-
णाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों
का वेतन अपने खरोदने की शक्ति में घटता
जा रहा था, उनका जीवन स्तर नीचे आ
रहा था, इन परिस्थितियों में केन्द्रीय
सरकार के कर्मचारियों के सम्मुख इसके
सिवाय और कोई चारा नहीं था कि वे
महंगाई भत्ते को महंगाई से जोड़ने की मांग

188 RS—1.

करते। यह मांग न्यायोचित थी और
वास्तव में वेतन आयोग की नियुक्ति
और उसकी सिफारिशों का सरकार
द्वारा स्वीकार किया जाना केन्द्रीय सरकार
के कर्मचारियों की इस मांग के औचित्य
को सिद्ध करता है। इस बात का प्रयत्न
हुआ था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी
हड़ताल न करें और मैं जानता हूँ कि
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के नेता
हड़ताल करने के लिये उतारू नहीं थे।
लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनीं और
शासन ने ऐसा रवैया अपनाया कि हड़ताल
को टाला नहीं जा सका।

आज मुझे स्वर्गीय श्री फीरोज़ गांधी का
स्मरण आता है जिन्होंने केन्द्रीय सरकार
के कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के
लिये और जब बातचीत टूटने की स्थिति
पैदा हो गई तो समझौता कराने के लिये
सारी शक्ति लगा दी लेकिन उन के प्रयत्न
भी सफल नहीं हुए और केन्द्रीय सरकार
के कर्मचारियों ने हड़ताल की। उस
हड़ताल को शासन ने अवैध घोषित किया,
हड़ताल को विफल बनाने के लिये अध्यादेश
जारी किया गया, रेडियो, समाचार पत्र
और प्रचार के अनेक साधनों द्वारा हड़ताल
को विफल करने की कोशिश की गई
लेकिन इतनी बड़ी संख्या में केन्द्रीय सर-
कार के कर्मचारियों का संगठित विरोध
प्रदर्शन एक बहुत बड़ी बात थी। कोई
हड़ताल से सहमत हो या सहमत न
हो लेकिन इस बात से इंकार नहीं कर
सकता कि हमें उन परिस्थितियों की
पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिये जिन में
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल के
लिये विवश हो जायें।

सभापति महोदय, एक लम्बी कहानी
है जो हड़ताल के बिला शर्त वापस लेने
के बाद समाप्त हो जानी चाहिये थी।
हड़ताल की समाप्ति के बाद शासन की

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

और से जो घोषणायें की गईं उन से इस बात का संकेत मिलता था कि यद्यपि शासन ने हड़ताल को पसन्द नहीं किया किन्तु हड़ताली कर्मचारियों के प्रति वह उदारता की नीति अपनायेगी। स्वर्गीय वडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने इस सदन में और दूसरे सदन में जो घोषणायें कीं उन से कर्मचारियों को आश्वासन मिला था कि केवल उन मामलों को छोड़कर जिन में कि कर्मचारी हिंसा करने के, तोड़-फोड़ करने के या घोर दुर्व्यवहार करने के दोषी हैं, सभी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति से काम लिया जायगा और हड़ताल के कारण जो एक कटुता पैदा हो गई थी—जो कि किसी भी स्थिति में वांछनीय नहीं कही जा सकती—वह कटुता समाप्त हो जायगी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी शासन के साथ मिल कर राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देंगे। लेकिन, यह बड़े खेद की बात है कि सदन में वरिष्ठ मंत्रियों ने जिन नीतियों की घोषणायें कीं उन को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया। अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है कि जो नौकरों से निकाल दिये गये हैं; जिन्हें या तो बर्खास्त कर दिया गया है या जिन्हें काम से हटा दिया गया है। ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से रिटायर किया गया है और जो कर्मचारी मुअत्तल हैं, जिन के मामले अभी तक विचाराधीन हैं, उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। माननीय गृह मंत्री जी ने २० मार्च को लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े रखे थे वे इस बात को बताते हैं कि अभी तक हम हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों और उन के नेताओं के मामलों पर ठीक तरह से निर्णय नहीं कर सके हैं। अभी तक शासन की ओर से यह नहीं बताया गया कि निकाले हुए

कर्मचारियों में से कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जो कि हिंसा करने के अपराधी हैं, कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने तोड़-फोड़ की है या घोर दुर्व्यवहार की परिधि में—जिसकी परिभाषा रेलवे बोर्ड ने अपने सरकुलर में की है—कितने कर्मचारी आते हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, इतनी बड़ी हड़ताल में कर्मचारियों ने बड़ी शांति से काम लिया। हिंसा की, तोड़-फोड़ की घटनायें नगण्य हैं। एक अंदाज के अनुसार तोड़-फोड़ से जो कुछ सरकार की क्षति हुई है वह केवल ४० हजार रुपये की है।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : और जो काम रोकने से हुई ?

श्री ए० बी० वाजपेयी : ऐसे मामले हैं जिन में कर्मचारियों ने हड़ताल के दिन काम किया, कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, जिस दिन हड़ताल हुई वह दफ्तर में उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति वहां अंकित है, मगर उन्हें निकाल दिया गया। ऐसे उदाहरण हैं जिन में हड़ताल में भाग लेने मात्र के ऊपर कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। हड़ताल में भाग लेना जुर्म नहीं हो सकता। आप अध्यादेश जारी कर के हड़ताल को अवैध घोषित कर दें लेकिन जब हम ने कर्मचारियों के काम करने के अधिकार को स्वीकार किया है तो काम न करने के अधिकार को भी स्वीकार करना होगा। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं और मुझे खुशी है कि जनमत के दबाव के कारण अंततोगत्वा सरकार को भी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये विधेयक लाने का

जो विचार था उसको त्यागना पड़ा है। हम अन्य देशों के उदाहरण देकर अपने कर्मचारियों के ऐसे किसी अधिकार को नहीं छीन सकते जो हम उन्हें पहले प्रदान कर चुके हैं। अगर नयी स्लेट पर लिखना होता तो हम नयी भाषा में नये अधिकारों का निर्माण करते, लेकिन जो अधिकार जो सुविधाएँ कर्मचारी आज तक उपयोग में लाते रहे हैं उन्हें अचानक वापस नहीं लिया जा सकता और इसलिये उपाय ऐसा करना चाहिये कि हड़ताल करने की परिस्थिति पैदा न हो। हम उन कारणों को समाप्त कर दें जिन से केन्द्रीय कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर किये जायें। लेकिन, आज की परिस्थिति में जब तक केन्द्रीय कर्मचारियों के हृदय में यह भाव मौजूद है कि उन के साथ न्याय नहीं किया गया, उन्हें अकारण दंडित किया जाता है, ऊपर से निर्धारित नीति का पालन नहीं होता और उन के जो निकट के अफसर हैं वे पुराना हिसाब चुकता करने के लिये हड़ताल का लाभ उठाना चाहते हैं। जब गृह मंत्री की धोषणाओं के बावजूद कर्मचारी संगठनों की यूनियनों को मान्यता वापस नहीं दी जाती और वे व्यवस्थित मामलों को अपने अधिकारियों के सामने रखने के अपने स्वाभाविक अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जब वे अपनी कठिनाइयाँ शासन के सामने रख नहीं सकते तो फिर जो भी असंतोष है, रोष है वह अंदर ही अंदर घुमड़ता है। अगर हम उसे अंदर से निकलने का कोई मार्ग नहीं दे सकते तो फिर वह विस्फोट के रूप में प्रकट होता है। अभी तक सब कर्मचारी संगठनों को मान्यता वापस नहीं की गई। कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल के अधिकार क्षेत्र में जितने भी विभाग आते हैं उन में से चार कर्मचारी संगठन ऐसे

हैं जिनकी मान्यता वापस नहीं हुई है, उनका अखिल भारतीय संगठन भी मान्यता से वंचित है। जब लोक सभा में प्रश्न किया गया कि आडिट विभाग में काम करने वाले और नौकरी से निकाले गये ६१ कर्मचारियों का क्या होगा, क्या उन्हें अपना मामला अफसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा, तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उन्हें एक एक मामला अपने अफसरों के सामने रखना चाहिये, उस पर बात करनी चाहिए। मैं उन के शब्दों को उद्धृत करता हूँ उन्होंने कहा था :

"They have to discuss. There is no way out."

जिसका अभिप्राय यह है कि आडिट विभाग के अधिकारी उन मामलों पर विचार करें, चर्चा करें कर्मचारियों को विश्वास में लें और अगर कोई ऐसे मामले हैं जिन में केवल हड़ताल में भाग लेने के लिये कर्मचारी नौकरी से निकाले गये हैं तो उन पर विचार करें। मगर गृह मंत्री जी की इस प्रकार की बात के बाद भी अभी तक आडिट विभाग के कर्मचारियों के मामले पर कोई गौर नहीं कर रहा। उन से बात तक करने के लिये कोई तैयार नहीं। भारत का संविधान कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल के सभी संबंधित कर्मचारियों को एक विशेष स्थिति प्रदान करता है। मगर अंततोगत्वा वे राष्ट्रपति के नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी हैं। कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल कर्मचारियों के मामले में परामर्श दे सकता है मगर वह निपेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। मुझे खेद है, गृह मंत्री महोदय अपनी बात अपने संबंधित विभागों से मनवा नहीं सके हैं और इसका कारण यह है कि जो भी वातावरण बदलना चाहिये था इतने दिनों में बदला नहीं है। स्वर्गीय पंत जी ने विल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि विभागीय कार्यवाहियाँ उन मामलों में

[श्री ए० बी० बाजपेयी]

होंगीं जहां कर्मचारी हिंसा, तोड़ फोड़ या घोर दुर्व्यवहार के दोषी होंगे । लेकिन पोस्ट्स एन्ड टेलीग्राफ्स में क्या हो रहा है ? १७,००० से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें हड़ताल में भाग लेने के लिये दंडित किया जा रहा है, जिनकी तनजुलियां कर दी गई हैं, जो मुअत्तिल कर दिये गये हैं, जिनकी तरक्कियां रोक दी गई हैं । एक एक कर्मचारी हर महीने ८० रु० का घाटा उठा रहा है । ऐसे मामले मौजूद हैं जिन में जो दंड दिया गया उस के अनुसार दंडित कर्मचारी आगे आने वाले सालों में १०,००० रुपये से वंचित हो जायगा । यह साधारण सजाएं नहीं हैं । आज की स्थिति में जब महंगाई बढ़ रही है और उस महंगाई का दुष्प्रभाव रोकने के लिये सरकार स्वयं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिये तैयार हुई है, हम सैकड़ों कर्मचारियों को उनकी तरक्की से वंचित कर दें, उन के आगे बढ़ने के मार्ग को रोक दें, उनकी सविस् का जो रिकार्ड है उसको खराब कर दें तो कर्मचारी यह मानकर नहीं चल सकता कि उन के प्रति शासन का दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज केन्द्रीय कर्मचारियों से संबंधित सभी मामलों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है । आम चुनाव के बाद नयी सरकार बनी है । है तो पुरानी बोल में पुरानी खराब ही, मगर नयी सरकार के रूप में हमारे सामने आई है और हमें आशा करनी चाहिये कि जो नीतियां निर्धारित की हैं उन मूल नीतियों को मैं बदलने की मांग नहीं करता—लेकिन वे मूल नीतियां अगर ठीक तरह से कार्यान्वित की जायं तो केन्द्रीय कर्मचारियों में एक एक भी सरकारी कर्मचारी ऐसा न रहेगा

जिसे नौकरी से हटाना पड़े । जो निकाले गये, जिन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, उनके एक एक मामले पर हमने चर्चा की है, आपस में बातचीत की है और सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अंतर्गत वे कर्मचारी आना चाहते हैं । आडिट डिपार्टमेंट में तो कोई सैंवोटोज नहीं हुआ है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, कोई हिंसा नहीं हुई है । ६१ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें हड़ताल में भाग लेने के अपराध में नौकरी से अलग कर दिया है । मैं रेलवे के मामले जानता हूं । लखनऊ के रेलवे के कर्मचारियों से मेरा निकट का संबंध है । वहां के अफसर किस तरह से प्रतिशोधात्मक मनोवृत्ति से काम कर रहे हैं यह मैंने पुराने रेल मंत्री के सामने रखा था । समय समय पर मैं उसे सदन में भी उपस्थित करता रहा । मेरी समझ में नहीं आता कि एक ही प्रकार का दोष करने वाला कर्मचारी भिन्न-भिन्न प्रकार के दंडों से कैसे पुरस्कृत किया जा सकता है । मगर ऐसे उदाहरण हैं जहां नीचे के अफसरों ने मनमानी से काम लिया है, ज्यादाती से काम लिया है और अगर ऐसे मामले दबे पड़े रहें और हम कहें हड़ताल की थी तो उसकी मजा भगतनी होगी तो यह कर्मचारियों के हृदय में कोई ठीक तरह से कर्तव्य निभाने की भावना पैदा नहीं कर सकता । मैं जानता हूं, लखनऊ के कुछ रेलवे कर्मचारियों के नेता जो हड़ताल के दिनों और दो दिन पहले मेरे साथ बैठे थे उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि वे जेलों में गये और उन्होंने रेलवे मंत्री की अर्थी जलाई । यह आरोप सरासर गलत है । वे नेता मेरे साथ बैठे थे । हम लोग कार्यालय में बैठकर हड़ताल की योजना बना रहे थे । यह ठीक है कि जो जलूस निकला उसमें अर्थी निकली, और किसी केन्द्रीय मंत्री की अर्थी जले मैं इसे पसंद नहीं करता और

बाद में जो जन समा हुई थी उसमें मैंने स्पष्ट शब्दों में इस बात की निन्दा की। लेकिन जो हड़ताल थी वह कर्मचारियों की हड़ताल नहीं थी, उसमें लखनऊ के जितने मेहनतकश थे, धर्मजीवी थे, सभी केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल की सहानुभूति में इकट्ठा हो गये थे। अर्थियां जलाना, यह पुरानी परम्परा है, जो हमें उत्तराधिकार में मिली है। बुजुर्ग नयी पीढ़ी को इसके लिये दोष नहीं दे सकते। फिर भी, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन जिन केन्द्रीय कर्मचारियों के नेताओं के ऊपर अर्थी जलाने का आरोप किया गया है वे जलूम में नहीं थे, अर्थियां बनाने में या जलाने में उनका हाथ नहीं है। मगर क्योंकि उन्हें हटाना है, ट्रेड यूनियन आंदोलन को शायद समाप्त करना है, उसका गला घोटना है इसलिये उनको अपना सिकार बनाया गया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, उन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया है। मैं नहीं समझता कि स्वयं रेलवे मंत्री या केन्द्रीय शासन इस प्रकार की नीति का अवलम्बन चाहता है। आज तक की घोषणा इसके विपरीत है। तो क्या मैं यह समझ लूं कि जो मंत्री सदन में बैठकर एक घोषणा करते हैं वे नीचे के आफिसरों को इस तरह की नीति पर चलने के लिये विवश नहीं कर सकते? हमारा मंत्री इतना असमर्थ और अशक्त तो नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जो घोषणाएं की हैं उनका ठीक तरह से पालन कराएं, एक एक मामले को देखें और इस बात के परिणाम पर पहुंचें कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो सचमुच में नौकरी से अलग करने के लायक हैं। मैंने इतना निवेदन किया है कि अगर एक एक मामले को देखा जायगा तो फिर जो कर्मचारी निकाल दिये गये हैं, जिन्हें नौकरी से अलग कर दिया गया है, उनमें ऐसा एक भी कर्मचारी नहीं निकलेगा

कि जिसे नौकरी से हटाने की आवश्यकता पड़े।

लेकिन अगर हम कर्मचारियों के मामले को एक एक रूप में विचार नहीं करेंगे, उच्च स्तर पर उसकी जांच नहीं करेंगे, छोटे अफसर पुराने हिसाब को चुकता करने के लिए कर्मचारियों के भाग्य के निर्णय के अधिकार को छोड़ नहीं देंगे तो कर्मचारियों को न्याय प्राप्त न होगा, न ही हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर शासन और कर्मचारियों के संबंधों में एक नये अध्याय का श्रीगणेश करना है तो उस हड़ताल के दुष्परिणामों पर आज एक मरहम लगाने की आवश्यकता है। आज उन कर्मचारियों के मामलों पर एक मानवीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। ये कर्मचारी शासन के प्रति निष्ठावान हैं और हड़ताल कोई राजनीतिक कारणों से नहीं हुई थी बल्कि बढ़ती हुई महंगाई ने कर्मचारियों के जीवन को संकटग्रस्त बना दिया था, इस कारण कर्मचारियों ने अपना असंतोष प्रकट किया था और हम उस असंतोष को दूर करने का मार्ग निकालें। लेकिन शासन ने चुन चुन कर कर्मचारियों के नेताओं को सजा देने की छट ले ली, फिर भी सरकार यह आशा करे कि वे शान्ति के साथ व्यवहार करें तो उसको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं इस प्रस्ताव द्वारा शासन से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे सभी कर्मचारियों को जिन्हें पिछली हड़ताल में निकाल दिया गया था, जो अपनी नौकरी से हाथ धी बैसे हैं, उन्हें फिर से काम पर वापस ले लिया जाय। यदि इस प्रस्ताव को इस रूप में स्वीकार करना शासन के लिए सम्भव न हो तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि शासन एक ट्रिब्यूनल नियुक्त करने के प्रस्ताव को माने जिसे नौकरी से निकाले गये सभी कर्मचारियों के मामले सौंप दिये जायें। मैं

[श्री ए० बी० बाजपेयी]

यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि अगर सदन अपने तीन सदस्यों की—भले ही वे सत्तारूढ़ दल के हों—एक समिति नियुक्त करे और उस समिति के सामने सभी निकाले गये, दंडित कर्मचारियों के मामले सौंप दिये जायं तो वह समिति जो फैसला करे वह फैसला हम को मान्य होगा और कर्मचारी उसे स्वीकार करेंगे। इस तरह से एक समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव को शासन स्वीकार करे। लेकिन यदि शासन इस संबंध में अपनी निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित नहीं करता, यदि वह एक एक कर्मचारी पर विश्वास पैदा नहीं करता, शासन उनके प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण नहीं रखता, उनके साथ न्याय करने को तैयार नहीं है, तो मेरा निवेदन यह है कि यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। इस तरह का दृष्टिकोण हमारे कर्मचारियों को परिश्रम की पराकाष्ठा करने की प्रेरणा नहीं दे सकता है। अगर आज आप विकास योजनाओं की सफलता चाहते हैं तो उनकी सफलता कर्मचारियों के उद्बोध और सहयोग पर निर्भर करती है। रेलवे मंत्री जी ने कर्मचारियों को बधाई दी कि उन्होंने रेलवे को सफलता के साथ चलाया है। हर एक मंत्री जब अपने कर्मचारियों के संबंध में बोलता है तो उनकी कार्यकुशलता और परिश्रम की प्रशंसा करता है। लेकिन इकट्ठा होकर ये केन्द्रीय कर्मचारी शासन से न्याय नहीं पा सकें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन कर्मचारी संगठनों की मान्यता को अभी तक वापस नहीं किया गया है, वह मान्यता वापस होनी चाहिये और उन्हें अपनी कठिनाइयों को शासन के सामने रखने का मौका मिलना चाहिये। कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिये कि वह अपनी

नीतियों को बदले और अपनी नीतियों में सुधार करे। आज गृहमंत्री जी उपस्थित नहीं हैं अन्यथा मैं उनसे कहता। मैं आशा करता हूं कि मेरी सब बातें उन तक पहुंचा दी जायेंगी। इतना ही प्रयाप्त नहीं है कि अलग अलग मंत्रालयों की हड़ताल के बारे में उन्हें किसी बात का पता नहीं होगा? गृह मंत्रालय का यह निषेधात्मक रवैया ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय का काम सब को निर्देश देने और सलाह देने का है और यह देखने का है कि इन निर्देशों का ठीक तरह से पालन किया जा रहा है या नहीं। गृह मंत्रालय को इस संबंध में कदम उठाना चाहिये कि उसकी जिन नीतियों का पालन नहीं हो रहा है उनको पालन करने की तैयारी की जानी चाहिये और इस तरह से एक नये अध्याय का श्रीगणेश करना चाहिये।

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: There is one amendment. You may move the amendment without making the speech now.

SHRI V. M. CHORDIA (Madhya Pradesh): Sir, I move;

"That after the words 'lost their jobs' the words 'or who have been demoted' be inserted."

The question was proposed.

SHRI T. S. AVINASHLINGAM CHETTIAR (Madras): Mr. Chairman, this indeed is a Resolution under which lie very important principles of Government. When I first saw the Resolution, I thought that it could be that it is an appeal so made in the name of mercy but I was amazed to hear the speech of the Mover of this Resolution. But before I go into the prac-

tice, that obtain in the various States, various Governments of the world, let me first state as to what happened really on the facts of the case. Sir, with the little Hindi that I knew, which was reinforced and supported by a little translation of the speech by my hon. friend to my left, I understood from the speech that the strike was a very peaceful *one*. He said: '*Bade shanti men kam kiye*'. I should like to tell this House how peaceful it was. One does not know. This is a publication of the I.N.T.U.C. They are people who are interested in trade unionism. If I understood the hon. mover correctly, he said that it was a blow to the great trade union movement and no institution stood for the trade union movement as much as the I.N.T.U.C. and this is what they have to say:

"In fact the movement was least non-violent; violence was used and used in abundance. Neither it was a peaceful action by any standards; there was no strike where there was peace and no peace where there was strike. Whatever dislocation that was brought about during those five days in a few pockets, it was created by means which were not peaceful by any standard. Employees were physically obstructed, they were mobbed while on work, families of those employees who refused to join the strike were threatened and even assaulted, children were kidnapped to coerce their parents to join the strike. On the 11th July in a Railway Loco Workshop a number of hand bombs and acid bulbs were seized. Crackers were thrown on the employees in their place of work and in numerous places, bodily assaults were made on the persons who refused to join the strike. Several instances of deliberate attempts of sabotage to disrupt communications by cutting of cables, signal and telegraph wires and damaging of railway track were reported. Fire of railway engines was deliberately dropped or

caused to be dropped in number of places with the object of immobilising the engines and blocking the track. Eight cases of derailment due to sabotage were reported during the strike period. An attempt was also made through non-worker hirelings to try to dislocate the transportation and communications. Thus on a railway 5000 refugees were employed on daily basis just to squat on the railway track to prevent movement of trains."

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh) :
 From what he is reading, may I know?

SHRI T. S. AVINASHLINGAM
 CHETTIAR: This is a report of the strike by the I.N.T.U.C.

SHRI P. A. SOLOMON (Kerala): Is he aware that the I.N.T.U.C. is a puppet organisation created by the Home Ministry itself?

SHRI T. S. AVINASHLINGAM
 CHETTIAR: Does he not know that this was sponsored by the Communists?

SHRI A. B. VAJPAYEE: May I know if there is any evidence to show that these acts were not committed by *agents provocateur*?

SHRI T. S. AVINASHLINGAM
 CHETTIAR: This is the argument of all criminals. When a murder is committed, the defence is, how do you know whether it was not committed by somebody else?

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You will have an opportunity of answering later. Do not disturb him.

SHRI T. S. AVINASHLINGAM
 CHETTIAR: These are arguments which are given as a defence by all accused in trials. To say the least, there was nowhere any atmosphere of non-violence in that strike. They tried their best, but they failed to win over the large body of

[Shri T- S. Avinashilingam Chettiar.] workers. All glory to this large body of workers, for they said that they would stand by the Government, because the consequences of the strike would have been tremendous. I also heard the hon. Member say—and I hope I have understood him correctly—that there was no political motive behind it. Let us imagine for a moment, what would have happened if the strike had succeeded. If the strike had succeeded, it would not have been possible to run the Government. And if it is not possible to run the Government, then the Government ceases to work. The Ministers go out and the Government goes out and chaos will rule. And the people who wanted to get advantage out of this strike thought they could come back to power in a very back-door way. Sir, it is wrong to think that in a strike where Government servants are concerned there is no political motive, because it itself is political.

Now let me examine the various practices obtaining in the various States of the world. I am grateful to the Institute of Public Administration in Delhi, for I had asked them to examine the position and let me have a note and I am grateful to them for the dispassionate note that they have prepared. In it they have stated that the prohibition or restriction on strikes by Government employees exist in the following countries: Austria, Belgium, Brazil, Canada, Ceylon, Columbia, Equador, Finland, and various other countries also. Now let us take the constitutional position in some of the prominent countries of the world. Take the United States of America. There they have an Act known as the Taft-Hartley Act and I would like to read what the late President Roosevelt had to say on this Act. He says:

"All Government employees should realize that the process of collective bargaining, as usually understood, cannot be transplanted into the public service."

Further he says:

"Since their own services have to do with the functioning of the Government, a strike of public employees manifests nothing less than an intent on their part to prevent or obstruct the operations of Government until their demands are satisfied. Such action, looking toward the paralysis of Government by those who have sworn to support it, is unthinkable and intolerable."

Therefore, this Act was passed to prohibit strikes and it is called the Taft-Hartley Act, and it says:

"It shall be unlawful for any individual employee by the United States or any agency thereof including wholly owned government corporations to participate in any strike."

Sir, in this Act, the punishment that was meted out was dismissal. But later on they had another Act in 1955 which said that not only will the persons be dismissed but will also be considered guilty of a crime, a felony and punished under the Criminal Code. This is the law. Except in France where there is an exception, almost all the countries in the world have by law banned strikes by Government servants. The reason is that otherwise the Government will not run. Government servants are not in the same position as other servants or workers in other establishments. Keeping this in view, where do we stand? It is quite clear that not only was this strike illegal but harmful. It was illegal. An ordinance was issued and it was made illegal. They were told in the strongest terms that the fullest punishment would be meted out to the strikers and they were warned. It is not as though they were not warned. They were warned and they were also told of the consequences by no less a person than the Prime Minister who did so on the radio so that everybody could hear it. Still they went on strike. And what happened later on? The strike failed dismally. They wanted to stop trains.

but they were surprised to find that the trains continued to run. They wanted to stop the functioning of offices even in Delhi. But to their surprise they found that the offices continued to work fairly normally. And then they surrendered. And what action did the Government take after they surrendered? I think, if I understood the hon. Member correctly, he said that they were treated very harshly, that they were treated very unsympathetically. But what are the facts of the case? Mr. Chairman, 45,945 persons struck work, and all except 208 have been reinstated. Does that show harshness? Does it show that Government treated them unsympathetically or does it show graciousness on the part of the Government? I know that when the Government later said that these persons should be treated sympathetically some departmental heads protested and said: "When the strike began we were told that we should take strong action. But when we take strong action, you don't support us, you support the strikers." I know some departmental heads said that. Still the Government said, let us be sympathetic. And the result is that all except these 208 have been allowed to join back and they have been reinstated. Out of these 208, 136 employees have either been dismissed or removed from service, 11 compulsorily retired from service and the rest 61, have been discharged from service. These are the details. Strong disciplinary proceedings were originally instituted against about 46,000 employees; 2,084 were dismissed or removed and 2,131 were discharged from service. The number of those in whose cases orders of dismissal, removal or compulsory retirement or discharge are still pending is very small, namely, 208. May I ask whether you consider this harsh? I think this is being very sympathetic.

I would like to add one more word and it is this. We who are interested in building up the democratic tradi-

tions in this country, we who are interested in building up a stable government in this country, we do feel that public servants should be kept satisfied, that they must have ways of putting forth their difficulties and removing them. We know that we must have the necessary machinery for removing their grievances. Everywhere there must be, and there are bound to be, difficulties and grievances and these difficulties must be looked into and removed. But is it by a strike that you are going to remove those difficulties? Direct action is not the method by which it can be done. As has been suggested, there must be bodies constituted with representatives of the Government and the government employees and they must sit down and thrash out problems and solve them. Institutions on the lines of the Whitley Councils have been suggested. There are a variety of other ways in which people can get together and understand these problems and solve them. All these have been suggested. I understand that and I feel that the Government should keep its servants comparatively happy, comparatively secure and comparatively free from difficulties. That is being done. It cannot be said in this country that we are not meeting their needs. Let us compare the conditions of employees in industrial establishments and those of the employees of the Government. Let us see the condition of people in private employment and the condition of the Government employee. Even today the number of people who seek government employment is tremendous compared to the number of people who seek private employment, because they think and know that government service is superior, that the government employees have provident funds, pensions, security of service and so on. Even mediocre people can flourish in government service. Outside, people have to compete with others, but mediocre men can sometimes *go right* up to the top in government service. There is security of service in govern-

[Shri T. S. Avinashilingam Chettiar.] ment service. Also the Central Government employees are much better off than those of the State Governments. This has been pointed out many times. Take the Madras Government and the pay scales of the Central Government and those of the Madras Government. Two brothers of the same family, with the same qualifications, the one in the Central Government is much better off compared to the other in the State service. The difference is so large. So I say that it would not be correct to say that government service is not attractive in this country and certainly it cannot be said that Central Government service is not attractive in this country. It is the highest-paid in the country and after all this, to say that they are being illtreated is just heartrending. I do not mean to say that they have no grievances. Of course they have. The prices have gone up and they are rising. We know that and we appreciate it. But to try to solve these problems by a strike is against all canons of public administration. No country which wants to maintain peace, which wants to maintain a stable government, can support such methods on the part of its servants.

Sir, in this House as well as in this Parliament, in our Houses, usually we suffer from one disability. We have Oppositions and the Oppositions can never come to power in the near future. I want a strong Opposition, Mr. Chairman, for they would be more responsible in that case. Oppositions which never expect to come to power cannot have a sense of responsibility and, with all due deference to the hon. Member who delivered the speech, I should say, if they had a greater sense of responsibility to the Government and to the people of this country, to the proper running of a Government in this country, the arguments which were advanced would never have been advanced. Sir, I oppose the Resolution.

श्री नवाबसिंह चौहान (उत्तर प्रदेश):
अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन के सामने पेश किया है, उसका वास्तव में क्या मतलब है, इसको वह स्वयं जान सकते हैं। इसके अर्थ अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार सब लोग लगा सकते हैं और मैं भी अपनी भावना के अनुसार इसका अर्थ लगाऊंगा। किन्तु एक बात के लिये तो वह प्रशंसा के पात्र हैं ही। आज देश में बहुत सी पार्टियाँ हैं, बहुत से दल हैं, जो किसान, मजदूर, विद्यार्थी व सारे समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। हम देखते हैं कि इसके आधार पर किसानों में भी दल बना दिये गये हैं, विद्यार्थियों में भी हिन्दू, मुसलमान, आदि नामों के आधार पर दल बना दिये गये हैं। इसी तरह से बहुत सी जगह मजदूरों को भी बांटने की कोशिश की जा रही है, किन्तु यहां वाजपेयी जी ने आज हिन्दू, मुसलमान या और किसी की बात न कह कर के सारे मजदूरों के लिये, जो कि निकाले गये हैं, सम्मिलित ढंग से कहा है। तो इसके लिये हम, आप और सभी लोग उनकी प्रशंसा करेंगे।

स्ट्राइक हुई और उसका क्या कारण था और क्या नहीं था? कुछ लोग जो यह कहते हैं कि इसकी मंशा राजनैतिक थी, वह भी ठीक है और साथ ही साथ जो यह कहते हैं कि राजनैतिक नहीं थी उनको भी आंशिक रूप से ठीक कहा जा सकता है। हां, जब आप यह बात कहते हैं तो जो दल, जो राजनैतिक पार्टियाँ स्ट्राइक में मदद कर रही थीं उनके बारे में आप कुछ कह सकते हैं। राजनैतिक पार्टियाँ किसी उद्देश्य से बनती हैं और किसी उद्देश्य से ही किसी की मदद करती हैं, किन्तु जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं यह मानता हूं कि उनमें थोड़े से अवश्य ऐसे हो सकते हैं, जो किन्हीं राजनैतिक विचारधाराओं से प्रभावित

रहे हों, लेकिन अपने तजुबों से, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनमें बहुत भारी संख्या ऐसे लोगों की है, जो किसी भी राजनैतिक पार्टी के प्रभाव में नहीं हैं। वे अपने स्वार्थों को लेकर चलते हैं और अपनी समस्याओं के कारण ही स्ट्राइक करते हैं या नहीं करते हैं। तो भी जो स्ट्राइक हुई उसमें बहुत सी राजनैतिक पार्टियों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। हमारे कम्युनिस्ट मित्र थे, पी० एस० पी० के लोग थे, इत्यादि। कम्युनिस्ट तो बड़े चतुर व्यक्ति होते हैं, वह तो ऐसे किनारे पर चलते हैं कि अगर कोई आन्दोलन सफल होता दिखाई दे तो उसका सारा श्रेय खुद ले लें और अगर गिरता हुआ दिखाई दे, तो एक धक्का खुद लगा दें और दूसरे के सिर पर उसका दोष दे दें। यही हाल था यहां भी, वह किनारे किनारे चल रहे थे। जब पंजाबी सूबा आन्दोलन चल रहा था, तब वहां भी वह किनारे किनारे चले और जब देखा कि आगे चलता नहीं है तो उसकी बुराई करने लगे। उसी तरह से यहां भी जब देखा कि यहां गड़बड़ होने वाली है, तो उन्होंने पी० एस० पी० को आगे कर दिया। अगर श्रेय मिलता होता तो जरूर आगे आकर इस बात को करते। मैं इस बात को मानता हूँ कि राजनैतिक दल, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उनकी मंशा जरूर राजनैतिक थी, लेकिन यह भी मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अधिकतर कर्मचारियों की—जिन्होंने हिस्सा लिया अथवा जो अंदरूनी तरीके पर स्ट्राइक से हमदर्दी रखते थे—उनकी मंशा राजनैतिक नहीं थी। यह तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कुछ राजनैतिक पार्टियों के लोग भी हो सकते हैं जो कि सर्विसेज के अन्दर हों और जिन्होंने स्ट्राइक में हिस्सा लिया हो—यही नहीं कि नीचे स्तर पर ही ऐसे लोग हों बल्कि बड़े बड़े अफसरों के अन्दर भी ये लोग मिल सकते हैं।

तो स्ट्राइक हुई और जिस ढंग से स्ट्राइक की योजना बनाई गई, वह सामने आई और

सरकार ने भी उसको खतरनाक समझा और बहुत से समझदार लोगों ने भी उसको ठीक नहीं समझा। जैसा कि हमारे चेट्टियार साहब ने कहा कि मिजरेविली फेल हुई और कोई यह भी कह सकते हैं कि काम-याब हुई, लेकिन जब हम कर्मचारियों की और सरकार की बात कहते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि इधर से या उधर से दोनों पक्ष विरोधी शक्तियों की बातें कर रहे हैं। हम यह नहीं समझते कि सरकार हो या मजदूर हो या किसान हो या और कोई हो, सब एक ही भारतमाता के हैं, उसी के अंग हैं। जब हम इस ढंग से सोचेंगे कि एक शहर हमारा शहर है, एक जाति हमारी जाति है, एक वर्ग हमारा वर्ग है, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर मजदूर को नुकसान पहुंचता है, दुःख पहुंचता है, तो गवर्नमेंट का हृदय भी उससे थरथरा जाता है और अगर मजदूर गलती करता है तो उसको गलती का अनुभव करा के उसको ठीक करने की कोशिश करना है, यह भावना होनी चाहिये। अगर यह भावना नहीं होती है, तो फिर चाहे सरकार हो या चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, कोई हो, देश का काम चल नहीं सकता है और देश को बहुत भारी हानि हो सकती है।

खैर, स्ट्राइक के बाद बहुत से लोगों पर कार्यवाही की गई और जिन पर असर पड़ा, वे लगभग ४६ हजार आदमी थे। मेरा सम्बन्ध भी पी० एंड टी० से बहुत दिनों से है, उनकी यूनियन से सम्बन्ध रहा है और उनके भी लगभग १७ हजार आदमियों के ऊपर असर पड़ा है। सरकार को—जो कि जनता की सरकार है—उसको भी अपने कर्मचारियों की भावना का ख्याल रखना है। उसको समझना है कि किस भावना से प्रेरित हो कर—अपने स्वार्थ की वजह से या और वजह से—उन्होंने स्ट्राइक किया, लेकिन स्ट्राइक को रोकने के

[श्री नवाबसिंह चौहान]

माने यह नहीं होते हैं कि उनको तहस-तहस और बर्बाद कर दिया जाय, उनको नौकरी से निकाला जाय, जिससे कि उनके बच्चे भूखे मरें और इसलिये सरकार ने बड़ी उदारता की नीति बरती। उसने आदेश दे दिया कि जिन लोगों ने स्ट्राइक में हिस्सा लिया है, यदि वे इसके लिये पश्चात्ताप करें, तो उन पर फिर कोई कार्यवाही न की जाय। यदि उन आदमियों ने कोई तोड़-फोड़ के काम नहीं किये हैं, रेलवे को रोकने के लिये फिश-प्लेट्स इत्यादि नहीं हटाई हैं या ग्रास मिसब्रिहेवियर नहीं किया है—ग्रास मिसब्रिहेवियर क्या होता है यह भी बयान कर दिया गया है—तो ऐसी हालत में वे अगर बर्खास्त भी कर दिये गये हों, तो भी उनको नौकरी में ले लिया जाय। जो यह आदेश सरकार ने दे दिया, यह उदारता की बात थी और इससे ज्यादा महान् और कोई बात नहीं हो सकती है और इसके लिये माननीय गृह-मंत्री जी और सरकार, मैं समझता हूँ, प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन सवाल यह उठता है—जैसा कि वाजपेयी जी ने भी कहा और मुझे भी कुछ थोड़ा सा तजुर्बा है, इस चीज का—कि यह जो उदार भावना प्रदर्शित की गई थी, इस उदार भावना पर हमारे अधिकारियों ने उदारता के साथ अमल नहीं किया है।

आज यह कहा गया है, इधर से और उधर से, कि हमें कोशिश करनी चाहिये कि स्ट्राइक्स न हों। मैं तो यह समझता हूँ कि स्ट्राइकों के होने का एक यह भी कारण है कि हमारे बड़े बड़े अफसर छोटे छोटे कर्मचारियों के साथ हमदर्दी से काम नहीं लेते हैं। जितनी जेनरल स्ट्राइक्स होती हैं, उनमें चार्टर आफ डिमांड्स रखे जाते हैं, प्राइस इंडेक्स दिया जाता है

और सब कुछ दिया जाता है, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ उनके दिलों के अन्दर यह चीज भी रहती है कि बड़े बड़े अफसर उनकी सुनते नहीं हैं। अगर आप देखें और जांच करें तो मालूम होगा कि छोटी छोटी जो शिकायतें—जिनको कि अफसर नहीं सुनते हैं—होती हैं, उनसे ही कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता रहता है और जब असंतोष बहुत बढ़ जाता है, तो तमाम लोग सोचने लगते हैं कि हम सब को मिल कर के कोई चीज करनी चाहिये और उस वक्त बहुत सी गैर-जल्दरी या जल्दरी चीजें भी मांगों में शामिल हो जाती हैं और एक बड़ा बवंडर खड़ा हो कर के एक स्ट्राइक का, एक ग्राम हड़ताल का, समां बन्ध जाता है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन चीजों की भी जिम्मेदारी हमारे अफसरों की होती है। मैं ग्राम तौर से उनकी आलोचना नहीं करता हूँ। बड़ी नेकनीयती से और बड़ी हमदर्दी के साथ काम करने वाले अफसर भी होते हैं; लेकिन अक्सर ऐसे लोग देखे जाते हैं, जिनके दिमाग में अफसरियत की बू रहती है और हमारे आदेश और हमारी नीति चाहे कितनी ही उदारता से भरी हुई हो, उस पर ठीक तरह से अमल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं, संकट उपस्थित होते हैं। उनके व्यवहार से स्ट्राइक तक की नीबत आ जाती है। वही हाल अब स्ट्राइक के बाद भी हो रहा है। आपने तो एक चीज कर दी, उदारता बरती, लेकिन वहाँ पर यह उदारता नहीं देखी जा रही है। जिन्होंने स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लिया, उनके दिलों के अंदर भी और जिन लोगों ने स्ट्राइक की, उनके दिलों के अन्दर भी यही भावना है कि हमारे अफसर लोग उदारता के साथ काम नहीं ले रहे हैं, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। हमारे अफसर लोग सरकार का जो आदेश है, उसका ठीक ढंग से पालन

नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि होम मिनिस्ट्री का ही एक महकमा ऐसा है कि जहां सभी सरविसेज के मामलात आते हैं, निपटायें जाते हैं, वहां से बहुत कुछ उसली आदेश दिये जाते हैं। यदि आपने तमाम अलग अलग मिनिस्ट्रियों पर इस चीज को छोड़ दिया, तो यकीन रखियेगा कि महकमापरस्ती के कारण महकमे के अफसरों की बात पहले चलेगी। नीचे वाले की कोई नहीं सुनी जायेगी, चाहे बात कितनी ही जायज हो। इसलिये ये जो बाकी केसेज रह गये हैं उनको भी किसी तरीके से होम मिनिस्ट्री के महकमे को या विजिलेन्स महकमे को सौंप दीजिए या जिसको आप उचित समझते हैं। मैं जानता हूं, इसमें प्रोसीजरल दिक्कतें होंगी, लेकिन ऐसा तरीका जरूर निकालना चाहिये कि इन तमाम मामलात की निष्पक्ष सहकीकात हो जाय। दूसरे महकमे के आदमी स्वतन्त्र रूप से यदि इन चीजों पर विचार कर सकें तो आप यह पाइयेगा कि आपके आदेशों के अनुसार वह सब अपराधी नहीं हैं; क्योंकि मुझे मालूम है, जैसे कि अभी बहुत सी चीजें बतायी गई हैं कि कर्मचारियों के ऊपर गलत इल्जाम लगाये गये हैं। मैं जानता हूं कि आपके जो कंडक्ट रूल्स हैं उनमें ४(ए) में यह है कि स्ट्राइक नहीं होनी चाहिये, किसी डिमान्स्ट्रेशन में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा नहीं लेना चाहिये। तो स्ट्राइक नहीं करना चाहिये, ठीक है। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनी मान लिया है कि स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेन्च ने यह निर्णय दिया है कि जहां तक डिमान्स्ट्रेशन का सवाल है, उसका अधिकार है। किन्तु डिमान्स्ट्रेशन करने और स्पीच देने के अपराध में आपने पहले ही अनेक निर्णय कर दिये हैं। मैं आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि मैं जिस यूनियन का प्रेसीडेंट हूं, उसका जो जेनरल

सेक्रेटरी है, उसको कंपल्सरी रिटायरमेंट देकर निकाल दिया गया है और इस बात के लिये निकाल दिया है कि किसी जमाने में जब कि आपका आर्डिनेन्स भी लागू नहीं हुआ था, उसने कोई स्पीच कभी दी थी। उस आर्डिनेन्स से पहले की स्पीच पर उसके लिये कह दिया गया कि इसको कंपल्सरी रिटायर कर दो। उसने कोई हिंसा की बात नहीं की, कोई फिशप्लेट नहीं उखाड़ी, जेलखाने भी नहीं गया, जब कि और भी बहुत से लोग व जेनरल सेक्रेटरी पकड़ लिये गये थे।

श्री अकबर अली खान (आन्ध्र प्रदेश) : आपने उसे रोका नहीं ?
You did not control him as its President?

श्री नवाबसिंह चौहान : आप इजाजत देते तो मैं बंसा भी करता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे मामले हैं, जिनमें क्या एविडेन्स है, क्या नहीं है, यह कुछ भी न देख कर कार्यवाही कर दी है। आपके आदेशों को देख कर कहीं कहीं निर्णय नहीं किये जा रहे हैं, और इस चीज को खयाल में रख कर कार्यवाही की जा रही है कि मानों इसको किसी न किसी प्रकार निकालना ही है, हटाना ही है। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह की विक्टिम्स को अभी तक जो परेशान किया जा रहा है, इसके लिये किसी तरीके से कुछ उदार नीति का पालन हो। वैसे कोई बहुत ज्यादा मामले नहीं हैं, और गृह मंत्री जी ने कई दफे बताया था कि कुल ४६,००० मामले हैं और २०८ के करीब ऐसे हैं, जिनमें कर्मचारियों को निकाल दिया गया है या रिटायर कर दिया गया है। हमारे पी० एण्ड टी० में ८ मामले ऐसे हैं, वैसे २,००० आदमियों को कुछ न कुछ सजा दी गई है। यह संख्या बहुत कम है। लेकिन यहां कम या ज्यादा का सवाल नहीं है। यहां इकाई का कायदा नहीं लगना चाहिये

[श्री नवार्बसिंह चौहान]

कि ४६,००० से घट कर अब केवल २०८ ही रह गये हैं। सवाल तो यहां मानवता का, इंसानियत का है। एक आदमी भी शेष रह जाता है तो उसको भी तकलीफ होगी, उसके परिवार को भी कष्ट होगा; लेकिन यह अवश्य देख लीजिए कि कहीं उन्होंने राष्ट्र के विरुद्ध तो कोई काम नहीं किया है। थोड़ी बहुत बेवकूफी भी हो गई है तो आपको जमा करना चाहिये। सबसे बड़ा अपराध राष्ट्र विरोधी कार्यवाही करना है, देश के प्रति विस्वासघात करना है। जो लोग ऐसे हैं, जो दूसरे देशों से सम्बन्ध रखते हैं, उनके इशारों से चलते हैं, उनको आप न बर्खास्त करें। लेकिन इस बारे में भी जांच आप यदि पक्षपाती अफसरों पर ही छोड़ देते हैं तो वह विरोधी को कह देंगे कि फलां कर्मचारी विदेशों से सम्बन्ध रखता है। इसलिये जो कार्यवाही आप करें, एक स्वतंत्र एजेन्सी के जरिये से करें। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वे लोग आपकी दुआ कर रहे हैं, जो वापस ले लिये गये हैं वैसे ही बाकी लोगों की दुआ आप लेंगे। यही बड़ी अच्छी बात होगी और उसमें कोई हानि नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस रिजोल्यूशन की जो भावना है, उससे न माननीय मंत्री जी को, न सरकार को, न किसी और को ऐतराज हो सकता है और मैं तो यह कहता हूं कि जहां इतनी रियायतें उदार भावना से प्रेरित हो कर दिखलाई गई हैं, वहां थोड़ी और रियायत दिखाना कोई बहुत बड़ी असंभव बात नहीं है।

चलते चलते मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी जिन जिन यूनियन्स को मान्यता नहीं दी गई है, मान्यता छीन ली गई है, उसको फिर से प्रदान करना चाहिये क्योंकि कोई न कोई निगोशियेटिंग मशीनरी होनी चाहिये, जो सरकारी कर्मचारियों की विक्कतों को सरकार के सामने रखे। इसी पर क्यों जोर दिया जाता है कि इन ट्रेड

यूनियनों को रिकग्नाइज नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि जैसे आडिट डिपार्टमेंट की बात कही गई, अगर वहां तीन, चार क्षेत्रीय यूनियन्स की मान्यता छीन ली है, तो आप उन्हें मान्यता अवश्य दे देंगे। जहां तक डिसिप्लिन का ताल्लुक है, आप जैसे चाहें उनसे कड़ाई के साथ नियमों की बातों का पालन करायें। देश के प्रति जिसका जो कर्तव्य है, उसका भी पालन कड़ाई के साथ होना चाहिये और साथ ही साथ जिसका जो अधिकार है, वह भी उसको मिलना चाहिये। अगर इस तरीके से काम हुआ और ऊपर के अफसरों ने भी नियमों का पालन किया तो मैं समझता हूं उससे प्रशंसा ही मिलेगी। हिंसा की यहां चर्चा हुई, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं गान्धी जी के मतानुसार जब हम किसी को बुरा कहते हैं और तेजी से लताड़ते हैं तो वह भी हिंसा ही है। इसी प्रकार अगर किसी के ऊपर हम नाजायज दबाव डालते हैं तो वह भी मेरे खयाल से हिंसा की कोटि में ही आ जाता है और मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय गृह-मंत्री जी कभी भी उस कोटि में आने की कोशिश नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI K. SANTHANAM (Madras): Mr. Charrman, it is a matter of regret that in his enthusiasm to sponsor the Resolution the hon. Mover should not have placed the facts squarely before the House. It is not true, as he stated, that the strike was precipitated by sudden economic difficulties of the workers because of rising prices. This was the case in 1957 when all the Central Government servants were greatly agitated and there were vague talks of strike but the majority opinion wanted a Pay Commission to go into the causes and the Government accepted the demand and appointed the Pay Commission in 1957.

This Commission reported in 1959. During its deliberations not a single labour leader, even of the Communist Party, questioned the impartiality or the competence of the Commission and when the Commission reported in 1959 there was general satisfaction about the new pay scales. There were cries of dissatisfaction only on minor matters because the Commission found that our workers were working too little and they cut down their leave a little and then abolished the half Saturdays and substituted one Saturday in a month. These were minor grievances. But somehow those people who in 1957 wanted to precipitate a strike thought that their influence was waning and so they wanted to get back their hold on the Central Government servants. For this purpose a convention was held in December, 1959 and there a Joint Council of Action was set up and they began to organise ballots for the strike. It was in response to their demand, a Pay Commission was appointed and the Pay Commission made unanimous recommendations. The Central Government had accepted their recommendations and were willing to implement them. In spite of all that some mischievous elements, who were leading these unions, wanted to precipitate another struggle. It was then that the Government had to decide what should be done. Therefore, the Prime Minister made an earnest appeal on 7th July that the Central Government workers should not indulge in these threats and should not go on strike. But his advice was not heeded. They went on strike on the 11th July. Those unions which had balloted for the strike were not unanimous. Even if their entire membership was taken into account, they constituted only one-third of the Central Government servants. Immediately before the strike, the President promulgated an Ordinance on 8th July and as soon as the strike began on the 11th July, orders were issued under the Ordinance making the strike illegal. Any

Government servant continuing a strike after it had been declared illegal was doing something which would upset any kind of Government, and much more so, a democratic Government. But then these people persisted and as my friend, Shri Avinashi-lingam, has pointed out, it was not at all a peaceful or non-violent strike. There were 122 cases of sabotage on the Railways and 31 cases of sabotage in the postal installations. There were many riots, as many as 244, in which 172 policemen and 29 volunteers were injured and 9 volunteers died. In spite of all these riots there were only 24 cases of police action in which five rioters were killed and 29 injured. My hon. friend stated that there was a loss of only Rs. 40,000. Was it not?

SHRI A. B. VAJPAYEE: Yes.

SHRI K. SANTHANAM: The loss to the Government amounted to Rs. 4½ crores.

SHRI A. B. VAJPAYEE: As a result of sabotage?

SHRI K. SANTHANAM: Sabotage and illegal strike. And there was a loss of 112 lakh man-hours. We have only just to imagine the amount of harm it had done to the national economy by the strike. Then, what happened? Soon the strike collapsed, because it could not be carried on. I know that in Madras the railway-men simply refused to join and all the trains, suburban and others, went on normally. In fact, this came as a sort of thunderbolt to the strikers there, to the strike leaders there. This was the case all over the country. Except in certain pockets, the large majority of Government servants were loyal and patriotic and they did not join the strike. As soon as the strike collapsed, of course, the Government wanted to go slow. Yet, they could not keep quiet. In 46,000 cases departmental action was instituted, as a result of which 2084 people were dismissed and 2136 people were

[Shri K. Santhanam.] discharged. But as a result of appeals from all kinds of people, both within the Congress and outside the Congress, that these people were misled and, therefore, they should be treated gently, most of these people were reinstated. There were only 20& cases of such people who had lost their jobs. One hundred and thirty-six people had been dismissed or removed from service, 11 people were retired and 61 people were discharged. All these discharged people are free to join Government service again. This is all the action which the Government have taken as a result of the strike in which such damage was caused and such loss was incurred by the nation. Therefore, to say that the Government of India have treated these strikers harshly is far, far from the truth. As a matter of fact, from the point of view of the well-being of the nation I think they have treated them very, very leniently. Here we must consider the principles involved. Is it right for a Government servant to go on strike? I think it is altogether wrong.

SHRI A. B. VAJPAYEE: The right is there in the Constitution.

SHRI K. SANTHANAM: No. There is no right in the Constitution that a Government servant can go on strike.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Order, order. Please go on.

SHRI A. D. MANI: As the cost of living was going up, why did you not pay them more?

SHRI K. SANTHANAM: The cost of living was covered by the new scales. The new scales of pay had covered the full rise in the cost of living. And whatever rise has occurred after the Pay Commission Report has been covered by the recent action. This strike action was taken when the cost was covered. It was wholly an anti-national and unnecessary strike that

happened in 1959. I think Government servants should n'ot have the right to strike. It is altogether immoral for a Government servant to go on strike, because he is a servant of the people. Against whom is he striking? Is it against the people, against the whole country? I think this ought not to be permitted.

And then, what was the nature of the strike? It was not an ordinary strike. It was not a sectional strike. It was a general strike. A general strike can certainly mean, more or less, a civil revolt, which is likely to become a violent revolt. We know what happened in Great Britain. The entire people rose against the general strike, even though it was led by the powerful Labour Party. We have not heard of a general strike in the United Kingdom afterwards. I hope hereafter we shall not hear any talk of a general strike by Government servants and if any such talk comes, the Government will take drastic action even before that talk is converted into any kind of action.

SHRI AKBAR ALI KHAN: That general strike in England was n'ot by Government servants. It was called by organisations of labourers, not directly by Government servants.

SHRI K. SANTHANAM: Including Government servants.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Yes, please go on.

SHRI K. SANTHANAM: It was supported by the Labour Party.

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh) : For that matter it was supported by Mr. Lloyd George.

SHRI K. SANTHANAM: Here, once the strike had been declared illegal, it was wrong on the part of the Government servants to have continued it. If Government servants themselves are to participate in an illegal action,

how can any law be maintained in this country or in any other country? Therefore, on principle, the Government could and should have taken more drastic action. Naturally they cared more for the human aspect and the action taken has been very mild indeed.

There is the argument of compassion. After all, we are not in a Communist country where all livelihood depends upon Government patronage. The Government servants form only a small minority of the community. How is it that 208 people cannot find an honest livelihood other than Government service? What is the great harm that these people have experienced? Is it the case that they are unfit to get any job other than Government service? Why should they not get their livelihood? Because they took the action, they must pay the penalty. When we, 'satyagrahis', went to jail, we never said: "All right. Please release us." We said: "We go to jail. We will take the punishment." So, when these people undertook the perilous task of organising a strike, they must be hold enough to say: "We took the risk. We do not care for Government service. We shall earn our livelihood by doing some 'other honest work.'" Sir, this argument of compassion is wholly mistaken.

Lastly, there is this basic issue of democracy. Is this country going to be ruled by the representatives of the people, or is it going to be ruled by the paid Government servants? That is the issue.

"[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

If by the threat of a Government servants' strike, general or partial, people are to be taxed more or if their finances are to be regulated by the threatening and bullying of their own servants, then I say democracy will not be worth the name. Government servants must be bound by

188 RS.—2.

decisions of the representatives of the people.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): They have trade union rights, they have constitutional rights. It was trade dispute on an outstanding matter.

SHRI AKBAR ALI KHAN: I think it is better that Mr. Bhupesh Gupta does not speak because we all know what happens.

SHRI K. SANTHANAM: I am glad that he has come. It was his Party that was responsible for the strike.

SHRI BHUPESH GUPTA: I see.

SHRI K. SANTHANAM: And now our 'other friends have taken up the cudgels. This is an unholy demonstration, I say. The whole idea behind the strike was that the Communist Party should mobilise its power over the workers both in the Government and outside the Government to stage finally not a peaceful strike but a violent revolution.

SHRI BHUPESH GUPTA: I thought that Mr. Santhanam was more intelligent than his words would suggest.

SHRI K. SANTHANAM: He would be less than a Communist if he says that his objective is not a proletarian revolution in the country. Is it your objective or not?

SHRI BHUPESH GUPTA: By this strike?

SHRI K. SANTHANAM: The strike was an infant step towards that ideal. Otherwise there was no justification at that time for this strike. It was only to consolidate the Communist power over Government servants, and I am glad it is broken, and I hope we shall not allow it to grow again among Government servants.

SHRI A. B. VAJPAYEE: The hon. Member should know that the strike

[Shri Ata] Behari Vajpayee.] was led by the Praja Socialist Party and not by the Communist Party.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar): Also by the Jan Sangh.

SHRI ARJUN ARORA: You say that it was led by the Praja Socialist Party. Then you admit that it was a political action and not a trade union move.

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam, I came here specially to participate in this debate because I think that we as representatives of the people in this House owe it to ourselves, to our c'onscience, to the Government employees and to the people at large that we take up this question with the Government and press for redress in this matter. It is pointless and it will serve no purpose on the part of hon. Members here if they try to raise some kind of political bogey and suggest that the strike was something like a proletarian revolution or that the Communist Party was behind the strike. This only shows that they have no case on merits. They need political diversion because everyone knows how the strike took place and what circumstances compelled the Government employees to take the decision much as they would have liked to avoid it. Who does not know that the Government refused to implement the recommendations of the First Pay Commission so far as increase in the dearness allowance with the rise in the cost of living was concerned? And Government employees were entitled to have it. Who does not know that they did not appoint the Second Pay Commission, and only when the Posts and Telegraphs employees gave the strike notice or wanted to give such notice did Government decide that the Second Pay Commission should be appointed? And it was appointed. That was how the workers had to fight for their demand.

Even before this thing came the Government employees were exploring the possibilities of negotiation, press-

ing their demands and So on and asking for a little redress. It was not done. But has not the Government itself proved by taking the subsequent action that fundamentally the case of the Central Government employees was abundantly just and honourable? Then why do y'ou accuse them? You cannot treat the country Or run the country in this manner when millions of Government employees are without housing, are remaining on starvation level and are demanding reasonable amenities of life. In such a situation d'o you expect our democratic institutions to flourish on the starvation and hunger of Government employees? What sort of democracy would it be if I were to: build that democracy on the skeletons of Government employees ground down in their day to day life? It would not be worth looking at. That is what I tell you. Therefore, it is an industrial dispute. Madam, let us not go back into its history. Everybody knows how it took place and how seventeen thousand Government employees were arrested in no time, in a matter 'of few hours, on mere suspicion or under charges most of which proved false in the courts of law or most of which had to be withdrawn. At the same time the Assam riots were taking place, and not one person was arrested under the Preventive Detention Act or any such thing. Are you serving democracy or are you wielding the big stick and trying to force the Government employees into submission? This question I may put to Mr. Santhanam when he says those things. Let us not go info these things; the strike was settled and we are all happy that it was settled. Shri Govind Ballabh Pant gave certain-assurances in the Lok Sabha on August 8th, 1960. I have got it here,, and this is what he said:

"We have issued instructions that those who had been arrested or those who had even been convicted or those who have even been suspended should be dealt with leniently and should be punished only to.

the extent it is necessary in public interest and io, the maintenance of discipline and efficiency and also for avoiding repetition of such scenes. That is what we wanted to do. And I can say that action has already been taken 'on these lines and large numbers have been already released or now allowed to resume duty, but there also the action taken by us is not final. We have now to devise methods so that there may be no strikes."

Then he went on elaborating this thing. He was speaking of lenient acti'on, mind you.

SHRI K. SANTHANAM: I am sorry my hon. friend was not present when I gave detailed figures to show how lenient the action has been.

SHRI BHUPESH GUPTA: Yes, but do not stop it.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): Whatever you may say, he just goes on.

SHRI BHUPESH GUPTA: Do not stop it. If you say lenient, go on with it. Leniency is not to be stopped. If it is an approach, a policy, an outlook or an attitude, there is no point in stepping away from it. On the contrary carry it out. This is what is expected bf you as the Government of the country by your own employees. Therefore I am asking you not to do something which is alien even to your practice. This is the point I wish to make.

Then again, in the L'ok Sabha, in answer to Unstarred Question No. 2223 on September 6th, the Home Minister gave a similar kind of assurance and so on. He was trying to say that he was dealing with this matter leniently. He was giving consideration to the demand 'that this thing should be set right and the people should be reinstated in their j'obs and so on. Everything we said he did not accept, but at the same time the debating point was not there—what Mr. San-thanam was saying, that the offence of

strike had been committed by them, so it must be an eye for an eye and a tooth for a tooth, and revenge must be taken on the Government employees. That was not the appfoach of the Home Minister of the country. His approach in this matter was that he should be more lenient. He did not fully accede to everything, but he realised, being a greater man, a wiser man than perhaps many hon. Members of this House, that here was a question of Government empl'oyees and it had to be treated not in a rigid, inflexible and oppressive manner but with compassion, sympathy and wise understanding. That is what he did. That he tried to do. After his death, some people seem to have taken advantage of it. I do not mean Shri Lai Bahadur Shastri for whom personally I have the greatest regard, and it is a tragedy today to see these Government employees not being reinstated when Shri Lai Bahadur Shastri, a great friend or disciple or whatever it is or a colleague of Pandit Govind Ballabh Pant ha, stepped into his shoes. I thought that he was a man more soft, more mild, and perhaps in many ways full bf human compassion. Therefore, at times I feel sorry for him. I am saying this thing not for flattery which is not my habit. You know it very well. I say what I believe to be true but somehow or other the bureaucrats sitting in the departments and the administration are advising him in a wrong direction. This is what I say.

SHRI SUDHIR GHOSH (West Bengal): How is this sort of a situation dealt with by the Government of the U.S.S.R.?

SHRI BHUPESH GUPTA: You go to the other planet. I am talking of India. I have gone to the U.S.S.R. Why don't you go to the moon? Get the American rocket and go there. (*Interruption*). Now, this is the position. He wants me go to the U.S.S.R. I am here in Indian Parliament today speaking.

[Shri Bhupesh Gupta.]

Now, Madam Deputy Chairman, it has to be reconsidered whether that matter is over, whether that thing has been settled. The goodwill of the Government employees is a precious heritage which the Government should cherish and if today people remain not reinstated in this manner and persecuted, it demoralises the administration. There will always be a feeling in the minds of the fellow-workers and employees that some of their men had been penalised, punished and persecuted because they had the courage to fight for the cause that was theirs. This is an objective consideration. It is not a subjective matter at all because whether an employee participated in the strike or not, everybody felt that he had a demand to put forward before the Government, a cause to fight for, and that naturally stands to reason. Those who fought for the cause and suffered for it are not criminals but valiant fighters for the cause of the working people, admired and appreciated even by those who did not participate in the strike. That you must bear in mind.

Therefore, by persecuting these people, by keeping them in their present position, you are at the same time annoying large sections of Government employees. All that we know. The situation is like that. Why should it be so? What do you lose by it? The Government of India, I should have thought, is something bigger than a petty police court or a petty police station. It is a much bigger institution than these and generosity shown in this matter would have brought, if anything, only credit to the Government and would have helped to reinstate good morale in the administration and also to win the goodwill of the Government employees. Why don't you do such a thing? What do you gain by it? Madam Deputy Chairman, Government employees have the right to strike as much as anybody has. The Constitution is not a Fascist Constitution yet.

SHRI AKBAR ALI KHAN: No.

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA: Yes, they have, they have.

AN HON. MEMBER: No.

SHRI BHUPESH GUPTA: Go to the Supreme Court.

(Interruptions)

You declared the strike illegal. The fundamental right is there and the Government employees have every right. If you had a Fascist Constitution, or would like to imitate President Ayub Khan or McCarthy or Hitler or Mussolini, I could understand it.

SHRI ARJUN ARORA: Or Khrushchev or Mao.

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA: I think you should be interested in Mr. Binoda-nand Jha more than in Mx. Ma'o. (Interruption from Shri Sheet Bhadra Yajee). He is popping up every time. He knows that what he says he will not believe. In the Lobby he will say that he does not believe it. But what can you do? Such is the drama that is enacted in this House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Carry on, Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: He must withdraw.

SHRI BHUPESH GUPTA: I do not withdraw.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: I want him to withdraw.

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam, in the Lobby he is a very good man.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: You withdraw. * * *

***Expunged as ordered by the Chair.

SHRI BHUPESH GUPTA: Why should I withdraw?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You carry on.

SHRI BHUPESH GUPTA: You are good in the Lobby. You are a very good man, I know. You are a good friend of mine in the Lobby.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI BHUPESH GUPTA: When I call him good, he gets annoyed. What can be done?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please finish your points. You have only three minutes more.

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam, Shri Yajee is my good friend; he is a very dear friend, more especially in the Lobby, I can tell you. He should not get annoyed like that.

Now, why should it be so? I think the matter should be closed. Shri Santhanam was saying: Can't they find jobs? Is it a question to be asked? Is it not cynicism, pure and simple? He has taken a fine job but what about the jobs to which they were entitled and in which they should be reinstated? Are you to take away the jobs and tell them to go and find jobs elsewhere? I cannot see any logic in it because they are Government servants. They have been Government servants. They want to be back in their posts. It is not a question of merely earning some money or getting something for their families . . .

SHRI K. SANTHANAM: Legitimate action was taken against them and they ceased to be Government servants. That action was taken.

SHRI BHUPESH GUPTA: I tell you, it does happen. People are reinstated; even in Government they are reinstated. Many suspension orders were withdrawn; many cases were

dropped. You have done it even in this particular case. I am not asking you to do something which you did not do. I am asking you to do something which you have done. Only I ask you to do a little more of this thing. You have dropped cases. You have reinstated people. You have stopped suspension orders. You have in some cases even condoned break in service. All these things are there. Why can't you in this case also do the same thing? This is what I ask. Am I asking you to do something which is unknown, alien and strange to you? Not at all. I follow this line.

Madam Deputy Chairman, we did not debate on this subject very much because views were known. We had divergence of opinion. We had different approaches in this matter. But ultimately this matter was settled; the strike was called off and you set in the process of reinstating people. You set in the process of meeting, as far as possible, some of their legitimate grievances, and what is more, there was a certain implementation of the recommendations of the Pay Commission—increase in their emoluments to some extent also. All these indicated that their essential case was just. When they had been subjected to such a denial, they took a certain action. I may call it an action taken in good faith and in pursuance of an industrial dispute, a justifiable action. You may call it, no, it was not a justifiable action. Here is a debating point, a point of divergence between us, a point of controversy. But after the strike was settled, I think the mind of the House was converging on one single point as to how not to persecute people but how to restore as many people as possible to their jobs. To that task the House addressed itself and the Home Minister at that time was thinking along this line. He was not thinking on the lines of prosecution, penalty, punishment, revenge. This is what I say. Now I say, let us stand on this pledge of a different, constructive, human

[Shri Bhupesh Gupta.] approach in this matter and try to see if we can bring ourselves to reinstating the remaining few men, some people who are still there. I do not see as to why it should be objected to in principle; I do not see as to why it should be opposed in practice; I do not see as to what standard of public justice or administrative decorum you lose by reinstating these men in their jobs and thereby helping their morale to be restored and also helping the people to be back to their posts and seeing that their families are not starved or put to unnecessary suffering. Now, this much thing cannot we expect from him? This much thing certainly we can expect from the Government. Do not bring in Communism here. Do not bring in parties here because you know how the strike took place. Now you are telling that the Communist Party is responsible for it. In the other House it was the P.S.P. Sometimes it will be somebody else. Put all these arguments aside; these are not relevant to the point at the moment today after two years of the strike or so. I appeal to the hon. Home Minister, Shri Lai Bahadur Shastri, in all solemnity that, in the name of the families of these men and for the sake of our trade union rights, and in the interests of democratic justice and in the interests of public administration, he should rise equal to the occasion and find his way to reinstate all these employees in their jobs, and carry forward the task which his predecessor, Shri Govind Ballabh Pant, began but could not complete, or maybe he had not thought that it should be completed in the manner I am suggesting now at that time. But the process was begun and let the present Home Minister complete it, and he will be earning their goodwill. Does he really believe that by punishing these people, putting them under penalty, he is going to win the goodwill of the Government employees? Will he take the plebiscite of the Government employees? He has got two million Government employees on the civil side. Is it his contention that if it were put

to vote to them in a plebiscite the Government employees will say: Punish them. I am sure, whether one participated in the strike or not, or supported it or not, every single Government employee in the country will give him the advice, if he were called upon to give such advice: Mr. Home Minister, please reinstate these people.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Abid Ali.

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore, Madam . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have called the next speaker.

SHRI BHUPESH GUPTA: Therefore, Madam, I have made this appeal and I expect Shri Lai Bahadur Shastri to do justice to these people.

SHRI ABID ALI (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, as you have called upon me to speak, I am bound to obey your order.

Now it is very interesting to find that the representatives of the Jan a Sangh and of the Communist Party have combined in this particular matter, one which is anti-national in every form and shape.

(Interruptions)

I am not referring to the Jana Sangh as being anti-national. No, no, not that way.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Are we going to ...

SHRI ABID ALI: Madam, if he hears me, he will be convinced that whatever I am saying is correct, and he will agree with me. They are only communal. Of course, it is communal. But communalism is also . . .

SHRI A. B. VAJPAYEE: Is it for the hon. Member to decide who is communal or not communal?

SHRI ABID ALI: But when I said "anti-national", I was particularly referring to the Communist Party.

SHRI A. B. VAJPAYEE: But he has not got the monopoly of nationalism in this country. What are we today on? Are we discussing today who is national and who is anti-national, and what is nationalism and what is not?

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam Deputy Chairman, we are not going to put up with this abuse of anti-nationalism. I would ask the leader, Mr. Lai Bahadur Shastri, to stop his reference to anti-national . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please proceed with your speech.

SHRI BHUPESH GUPTA: He starts the abuse by calling us anti-national. What does he mean? (*Interruptions.*) I would ask for your ruling whether the leading party in Parliament which is in opposition should be called anti-national from the Government side.

SHRI ABID ALI: There is no party.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI BHUPESH GUPTA: What is it then? Do you not know that we have received 12 million votes? What is it?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. The hon. Member will sit down when the Chair is on its legs.

SHRI BHUPESH GUPTA: I know, Madam, but please stop him from calling us 'anti-national'.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

SHRI K. T. SHAH: You obey the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. No hon. Member should be on his feet when I am on my feet, and I do hope you know the procedure.

SHRI BHUPESH GUPTA: I knew when he was chucked out of the Ministry, he would give us trouble.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Abid Ali, you will carry on with your speech and make your points without any insinuations.

SHRI ABID ALI: Now I was saying that the Jana Sangh . . .

श्री एम० गौरे (उत्तर प्रदेश) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या यह संसदीय परम्परा के अनुकूल है कि इस सदन के किसी सदस्य को कहा जाय कि वह अराष्ट्रीय है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please carry on.

SHRI ABID ALI: Nobody can say that there are no anti-national elements in this country. There are some. Every country has traitors . . .

श्री एम० गौरे : तो फिर उनको यहां से निकाल दीजिए ।

श्री आबिद अली : हाँ, उनको निकाल दें लेकिन कायदे के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वह की जायेगी ।

SHRI BHUPESH GUPTA: Nobody can say they are no agents of big capitalists who are chucked out by their Prime Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will not permit such interruptions. The hon. Member has had his say. He should be patient with other speakers, and if he has any corrections to make, he can make them later.

SHRI ABID ALI: Now coming to this particular Resolution, Madam, all employees including Government servants deserve sympathy and support so far as their legitimate claims are

[Shri Abid Ali.] concerned, and at the same time, Madam, Government also deserve unqualified support, unstinted support when it takes action in the interests of the country and to maintain discipline among the Government employees. Madam, it is very fortunate for this country that, by and large, the civil servants in this country are not only good, honest and dutiful, but are also patriots. At one time, four or five years back, when there was some agitation to attend to their duties without shirts, shirtless, at that time only four employees in the Delhi Secretariat thought of entering the outer precincts of the Secretariat without shirts, and going up and up the steps they found that all their colleagues were going with their shirts on and those four also went on putting their shirts, because the then Home Minister had appealed to and also warned them that action would be taken, and observed that there was no justification for the demonstration that they were attempting.

Our Government, with regard to this particular matter, has been very much liberal, has been considerate and has been in favour of the employees. On the other hand, there is the legitimate complaint that, so far as national interests are concerned, they should have behaved better and that this sort of indiscipline and this sort of strike was uncalled for. I am coming to the right to strike to which the hon. Member has made a reference. It should be thought over twice before it is attempted or preached.

Now some hon. Member said that the strike was settled. Who settled trike? Where were the negotiations, and with whom? The strike collapsed. Firstly, out of the two million Government employees hardly one-fourth, less than one-fourth, either went on strike or were forced to go on strike. A large number of them did not want to go on strike but they were forced by elements which became very much violent, and as has been pointed out by my hon. friend

from Agra, Shri Nawab Singb Chauhan . . .

SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN:
Aligarh.

SHRI ABID ALI: All right; I correct myself, but Agra is also in U.P.-

श्री ए० बी० वाजपेयी : आपको आगरा भेजा जा रहा है ।

श्री आबिद अली : वह भी तो हिन्दुस्तान में
The Communists remained aloof in the morning, were only watching the situation. Some of the friends of the P.S.P. or H.M.S., well, they were leading the strike, and the Communists were only watching. By noon, when it was clear that the strike had failed, the Communists, those who were watching and some of those who had resorted to the strike, well, they were the first to resume the strike, followed by others subsequently. Now, action was attempted against about 27,000—I am quoting from memory . .

SHRI A. B. VAJPAYEE: Forty-six thousand.

SHRI ABID ALI: Then it went on decreasing and decreasing, as it was mentioned this morning. Now, about 300 persons only are involved.

SHRI K. SANTHANAM: Two hundred and eight.

SHRI ABID ALI: There were a few, 2,000 perhaps, who were demoted, or action of a minor nature was taken against them. Now the hon. Member who moved this Resolution said that every person had been penalised simply because he went on strike. If this was the case, then there would have been about 4 lakh disciplinary actions. But this Government had been, as I have said earlier, very much considerate. The hon. Member who has just spoken said that they are starving. But, Madam, action should be taken against those who

commit breach of the law. Now, Madam, if a person commits a murder and his children go to court and say, "If my father is punished, then we will starve," then it means that no action should be taken against any criminal, against those who attempt to paralyse the Government, against those who attempt to create chaos in this country. Against those who commit crimes against the society or against the nation, certainly action should be taken against them to the extent that it becomes necessary in the interests of the country, its security and its integrity. But this sort of complaint has no basis so far as this particular case is concerned. There are political parties who are attempting penetration into Government services and I request the Home Minister, as he should be very much alive to this aspect also, to ensure that, of course, so far as opinion is concerned, everyone in this country, whether he is in government employment or otherwise, is entitled to have opinion. But when that opinion is attempted to be used against the interests of the nation, national interest should be protected, and any action which the Government may take in this behalf will have certainly, not only the support of the public but also of every sensible, genuine, Indian and Members of Parliament.

The Resolution in question is very much helpful to convince every reasonable-minded person that the Government has been, in this particular matter not vindictive. If they had been vindictive, a large number of persons would have been out of Government jobs.

Madam, about the staff in the offices of the Comptroller and Auditor-General, much reference was made by the mover of the Resolution who should also remember how much complaint is against them. What is the extent of discipline in that office, how much politics is discussed there and everybody knows how many months an ordinary file takes for its disposal

in that office. To that aspect also we should be alive.

About violence, much reference was made about the I.N.T.U.C. this morning. The hon. Member, Shri Chettiar, read extracts from the report of the I.N.T.U.C. and someone, there from the Communist Benches, said that it was an organisation of "Government stooges". Yes, it is easy to make such remarks, but perhaps the hon. Member who made this remark does not know that the I.N.T.U.C. did not come into existence after independence. The I.N.T.U.C. came into existence in Champaran when Gandhiji started his movement there, followed by a trade union organisation established by Mahatma Gandhi in Ahmedabad and which spread to Bombay, Indore, Jamshepur, Madras, Calcutta and so many other places. When the workers working in different spheres in different parts of the country thought that the question of achieving national independence was over, they thought that more attention should be devoted to help the workers, both peasants and those working in factories. They thought that a national organisation was necessary. As a matter of fact, it was already working, though not having come together technically. The day they decided to get together, they met and the unions of about eight lakhs of workers got affiliated to the I.N.T.U.C.

Madam, the I.N.T.U.C., which is very much alive to the needs and requirements of workers, is also alive to national interests. They know that if national interests are in jeopardy, where are the workers, where are the peasants? There will be chaos in the country. They know that national interest, national prosperity, comes first and from that everything else flows.

So far as the workers are concerned, the I.N.T.U.C. tries its best to secure all that the workers deserve. Now, when occasions come, when political parties for their own interest try to create chaos in this country and want

[Shri Abid AIL] to exploit the workers, it is the duty of the I.N.T.U.C. to protect them, to give them a proper lead. I am proud of the part played by the I.N.T.U.C. organisation, its workers, its leaders with regard to this particular strike. Every sensible, genuine, patriotic Indian will support the stand that this workers' organisation, this I.N.T.U.C., played its part very well. It was a political strike. It was not a trade union movement, it was not a trade union demand.

Madam, the Prime Minister had given the unqualified promise, which he has carried out also, that whatever award, whatever decision will be given, those recommendations made by the Pay Commission will be accepted as an award. After having got this unqualified assurance from the Prime Minister of the country, where was any room left for any action on the part of the leaders of the so-called Government employees' strike except that there was political motive behind it? That has been amply proved, and my request to the Government, particularly with regard to the strikers against whom action has been taken, is that in case a substantial case is made out that action has been taken against any particular employee who was really innocent, that should be given special consideration. But those who were responsible for sabotage, who were responsible for this unwarranted strike, of course, action against them is justified and it should be confirmed.

Again, there is one case which I would like to plead, namely, of those against whom action has been taken but who did not participate in the strike. There are some supervisors under the influence of a party which is very much anti-national, and there are some persons who are able to exert their influence in some of the De-fence establishments and in some other offices. They have been very much responsible for harming those persons who opposed this strike and against persons who preached violence.

Their women and children, their family members were attacked, and their property damaged. Their interest also is very much necessary to be protected by the Government. Their cases have been reported to the Government. I am sorry to say that those who stood by the nation, who stood against these anti-nationals, action has been taken against them and they are really victimised.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up.

SHRI ABID ALI: Only two minutes more, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You have taken more than two minutes.

SHRI ABID ALI: Because of the rights given to Government servants under the Constitution, the sense of fear is gone. I am happy that that sense of fear does not exist amongst Government servants, but there should be a sense of responsibility also. There are some elements amongst them, although a very, very small percentage, who are attempting to see that the sense of fear having gone, a sense of responsibility should not enter and there should be more cases of indiscipline. I submit to the Home Ministry that there is at the present time a vacuum, a sense of responsibility has not entered and the sense of fear having gone, they should rise to the occasion and find out appropriate ways and means by which this attempt to create chaos and indiscipline amongst Government servants is very much checked.

SHRI M. RUTHNASWAMY (CMadras): On a matter of information, may we know from some Government spokesman on what grounds these 200 Government servants have been dismissed and discharged?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI B. N. DATAR): These Government servants . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Minister may kindly make a note of it and may cover the point when he replies.

श्री चन्द्र शेखर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जिसको माननीय श्री बाजपेयी जी ने इस सदन के समक्ष रखा है। मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ है कि जब इस प्रस्ताव पर सदन में भाषण किये जा रहे थे। तो शासन की ओर से, उन पुरानी बातों को दोहराया जा रहा था जिन्हें बार-बार इस सदन में और देश के सामने रखा जा चुका है। यह बात फिर कही गई है कि यह जो हड़ताल हुई है वह एक राजनीतिक हड़ताल थी। हमारे एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि इस हड़ताल को कराने का श्रेय, इस हड़ताल को कराने की जिम्मेदारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर थी।

श्री अर्जुन अरोड़ा : प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यह काम नहीं कर सकती है। वह बहुत कमजोर है।

श्री चन्द्र शेखर : मैं आपके द्वारा उन माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कुछ सम्मानित सदस्य ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम करते हैं और उन्होंने हड़ताल के सिलसिले में जो कुछ किया उस पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अपने को गौरवान्वित मानती है। लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यह नहीं मानती है कि किसी राजनीतिक भोटिव से या किन्हीं राजनीतिक हितों को ध्यान में रख कर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने यह काम किया। आज बड़े जोरों से शासन की ओर से कहा जाता है कि जो गैर-कानूनी हड़ताल हुई उसे दबा दिया गया है

और इसके साथ यह भी कहा जाता है कि जो लोग गैर-कानूनी काम करेंगे उन्हें भी दबा दिया जायेगा। हमारे एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि हम में वह शक्ति है कि अगले आने वाले दिनों में जो लोग इस तरह की आवाज उठावेंगे उन्हें हमेशा के लिए दबा दिया जायेगा। मैं आपके जरिये उन माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मानवीय चेतना कभी भी बन्दी नहीं बनाई जा सकती, मानवीय परिन्दा कभी कफस में बन्द नहीं किया जा सकता। बड़े से बड़े शासन दुनिया में आये, बड़ी से बड़ी शक्तियां दुनिया में आईं, लेकिन वे मनुष्य की चेतना को कभी दबा नहीं पाईं। जो मनुष्य की चेतना आज बढ़ रही है, जो मानव की संवेदना आज जाग रही है, उसको दबाने की कोशिश अगर कोई भी शासन करेगा और खास तौर से जमहूरियत के अन्दर तो वह शासन मिट जायेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। माननीय रेलवे मंत्री जी, जो यहां बैठे हुये हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मजदूरों ने ग़लत किया या सही किया, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि गरीब मजदूरों के लिए जो आपका तरीका है, गरीब मजदूरों के लिए जो आपका जोश, शक्ति और हिम्मत है, क्या वही आप अपने शासन के उच्चाधिकारियों के लिए भी रखते हैं। यह रेलवे आडिट रिपोर्ट है। कोई भी माननीय सदस्य इसके पन्नों को उलट करके देखें, तो उनको हर पन्ने पर दस-दस, बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस लाख रुपये का ग़बन और ग़ैर-जिम्मेदारी से खर्च करने की बात दिखाई देगी। इस रिपोर्ट के १५ पेज पर लिखा हुआ है कि एक मामले में आठ महीने तक कोई आर्डर न देने की वजह से और रेलवे बोर्ड की कमजोरी की वजह से रेलवे प्रशासन का छः लाख रुपये

[श्री चन्द्र शेखर]

वरवाद हो गया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हड़ताल के कारण रेलवे का बड़ा भागी नुकसान हुआ। यह छः लाख पये की जिम्मेदारी जिस रेलवे बोर्ड के ऊपर है, मैं रेलवे मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस रेलवे बोर्ड के सदस्यों को मुआतिल किया जायेगा या उस समय जो माननीय रेलवे मंत्री थे, क्या उनको प्रशासन के लोग मुआतिल करने के लिये तैयार हैं। नहीं तैयार हैं। वे यह कहेंगे कि यह नया देश है, नया प्रजातंत्र है, जमहूरियत में हम नयी बातें सीख रहे हैं, इस लिए गलतियाँ होती हैं। हम थोड़े समय में सीख लेंगे। उच्चाधिकारियों के लिये यह बात कही जाती है। मंत्रियों के लिए यह बात कही जाती है। लेकिन यह बात नहीं कही जाती है छोटे कर्मचारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिये जो इस राष्ट्र को बनाने के जिम्मेदार हैं, जो इस देश के भावी निर्माता हैं।

हमारे एक माननीय सदस्य ने, जो उस समय में शायद श्रम विभाग के उप-मंत्री थे, बड़ी बधाई दी आई० एन० टी० यू० सी० को और उन्होंने एक नया इतिहास सीखने को कहा। उन्होंने कहा कि आई० एन० टी० यू० सी० का निर्माण स्वतंत्रता हासिल करने के बाद नहीं हुआ था, बल्कि चम्पारन के मैदान में हुआ था। इस प्रकार गांधी जी का नाम लिया गया चम्पारन की याद दिलाई गई। महात्मा गांधी जी और चम्पारन की याद करते समय मैं प्रशासन के लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ कि आजादी की लड़ाई किस बुनियाद पर हुई थी? गांधी जी ने कहा था कि एक बड़े से बड़ा आदमी इस देश को नहीं बना सकता। इस देश को बनाने की जिम्मेदारी इस देश के उन करोड़ों लोगों पर है,

जो भखे हैं, तबाह हैं, परेशान हैं। उनके मनोबल को उठा कर इस देश को तरक्की की मंजिल पर पहुँचाया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इन कर्मचारियों को निकाल करके आज प्रशासन इस बात का दोषी नहीं है कि गरीबों के मनोबल को दबाया जा रहा है? मैंने प्रारम्भ में कहा था कि यह चेतना जो बढ़ रही है, वह कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, कोई राजनैतिक स्वार्थ के लिए नहीं है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग राजनैतिक स्वार्थ रख सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग राजनैतिक स्वार्थ रख सकते हैं। लेकिन जो गरीब मजदूर अपनी रोटी के लिए मुहताज है, जो गरीब मजदूर अपने खाने के लिए मुहताज है, उसके सामने एक ही सवाल है कि उसको खाना मिले और वह इसी के लिए लड़ता है। क्या यह बात सही नहीं है, जैसा कि आप बार बार कहते हैं कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्या यह बात भी सही नहीं है कि कास्ट आफ लिविंग बढ़ने की वजह से जो मजदूरों का जीवन स्तर था वह सन्, १९४७ से लेकर १९६० के बीच में गिरा है? अगर ये बात हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किस के ऊपर है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की किसी प्राइवेट कंसर्न के कर्मचारियों से तुलना कर लीजिये। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संतोष करना चाहिये। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ आप के जरिये उन माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि अगर आप तुलना करते हैं एक सरकारी कर्मचारी से किसी दूसरे प्राइवेट फर्म के एक कर्मचारी की, तो फिर इस देश में एक माननीय मर्च के

खर्चों से एक गरीब के खर्चों की भी तुलना होनी चाहिये। अगर आप यह कहते हैं कि बिड़ला की किसी कंसर्न में कम पैसा मिलता है, तो क्या लीवर ब्रादर की कंसर्न में जो पैसा मिलता है वह आप अपने सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए तैयार हैं? इस तरह से कोई काम नहीं चलेगा। सीधासवाल तो यह है कि जिस चम्पारन की याद दिलाई गई, जिन भावनाओं से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, क्या हमें उन भावनाओं को बल देना है या उन भावनाओं को दबाना है ?

एक माननीय सदस्य ने, जो हमारे बड़े दोस्त हैं, बड़े जोरों से यह कहा कि खुश्चेव के राज्य में क्या होता है। अभी तक हम ऐसा समझते थे कि मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे माऊ को बड़ी मुहब्बत है। लेकिन अब मुझे यह जानकर आश्चर्य और दुख हुआ कि इस समय उस दल में ऐसे लोग भी हैं जिनको माऊ और खुश्चेव के आदर्शों और सिद्धान्तों से मुहब्बत हो गई है। मैं उन से कहना चाहूंगा कि हम माऊ के आदर्शों पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुश्चेव के आदर्शों पर चलने के लिये तैयार नहीं हैं। यह प्राचीन देश है। जिस देश की नस नस में स्वतंत्रता की भावना विद्यमान है, जिस देश में महात्मा गांधी जैसे आदमी पैदा हुये जिन्होंने यह काम किया कि बड़े से बड़े शासन के सामने, बड़े से बड़े साम्राज्यवाद के सामने गरीबों को उठा कर खड़ा कर दिया उस देश में ऐसी बातें कही जायें, यह कुछ अच्छा नहीं लगता। इस वजह से यदि किसी बात का माननीय वाजपेयी जी समर्थन कर रहे हैं, माननीय भूपेश गुप्त जी समर्थन कर रहे हैं, तो उस बात पर विचार करते समय हमें यह

बात नहीं कहनी चाहिये कि वे किस राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं। मैं यह समझता हूँ कि अगर ऐसी बात है तो उस तरफ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका समर्थन हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहा है। जैसा कि आबिद अली साहब ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्प्रदायिक हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र-विरोधी हैं और हर देश में ऐसे लोग होते हैं, तो क्या मैं यह कहूँ कि इस देश की सबसे बड़ी संस्था होने के नाते कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि इन सवालों पर विचार करते समय ऐसी बातें मत सोचिये।

इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि लीनएन्सी तो की गई। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि जिन स्थानों पर कोई हिंसा नहीं हुई, जहां पर कोई उपद्रव नहीं हुये, वहां भी लोगों को बर्खास्त किया गया, वहां भी लोगों को नौकरी से हटाया गया। मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगा, खास तौर से लखनऊ का। वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई लेकिन वहां कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। नार्थ ईस्टर्न रेलवे में ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जहां पर प्रशासन के लोगों ने यह कहा कि हमारे आदमियों को रख लिया जाय, लेकिन उच्चाधिकारियों की ओर से उस पर टालमटोल की गई। क्या ऐसे भी केसेज नहीं हैं जहां पर उनको नौकरी पर रखा गया लेकिन उस जगह से हटा कर उनको दूसरी जगह रखने की कोशिश की गई, जहां स्वास्थ्य के आधार पर उनकी मुस्तेदी नहीं हो सकती थी? ये सारे सवाल हैं कि कितनी बड़ी तादात में लोगों के ट्रांसफर किये गये, कितने लोगों के प्रोमोशन रोके गये, कितने लोगों को तनज्जुल किया

[श्री चन्द्र शेखर]

गया और यदि हम इन सवालों पर विचार करें तो हम इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि इस हड़ताल को देखते हुए यह बहुत बड़ा दंड दिया गया है।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि वह तो विद्रोह की अवस्था थी। दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि २० लाख कर्मचारियों में से केवल पांच लाख ने हड़ताल की नोटिस दी। प्रशासन की ओर से उस जमाने में कहा गया था कि हड़ताल मुश्किल से १० फी सदी लोगों ने की। मैं जानना चाहूंगा कि दोनों बातें कैसे कही जाती हैं। एक तरफ तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जाय और दूसरी तरफ प्रशासन यह कहे कि हड़ताल फ़िज़िल आउट हो गई।

श्री अर्जुन अरोड़ा : विद्रोह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वह नाकामियाब हुई।

श्री चन्द्र शेखर : स्थिति अगर नाकामियाब हो गई, तो मैं यह चाहूंगा कि अगर विद्रोह की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई तो जिन लोगों ने कोशिश की, उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करें। लेकिन आप यह मानेंगे कि आप यह खुद कहते हैं कि यहां का जो कर्मचारी है, वह विद्रोह करना नहीं चाहता, वह आपका बड़ा लॉयल है, आपका बड़ा स्वामिभक्त है, तो फिर उसको दंड क्यों दिया जाय ?

DEPUTY CHAIRMAN: I had called for the report as to exactly what Shri Sheel Bhadra Yajee had said. He has used a phrase which is unparliamentary. It will be expunged.

The House will now adjourn to meet again at 2-30.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA), in the Chair.

T
H
E

श्री चन्द्र शेखर : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इसके पहले जब मैं अपना भाषण कर रहा था, तब मैंने यह कहा था कि सरकार की ओर से यह कहा गया कि केवल २५ लाख लोगों ने हड़ताल करने का नोटिस दिया और उसमें से मुश्किल से ढाई लाख लोगों ने हड़ताल किया। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि एक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसको दवाने के लिये जरूरी था कि अध्यादेश जारी किया जाये। उस तरफ से कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार की ओर से जो दंड दिया गया, वह दंड बहुत कम था और सरकार बहुत ढिलाई से कर्मचारियों के साथ पेश आई। मुझे जानकारी है, मुझे बताया गया है कि केवल पोस्ट एंड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट में ही १,२६६ लोग ऐसे थे जिनके पद को नीचे गिराया गया और उनकी तनख्वाहों को कम किया गया। तो इतने लोग ऐसे थे जिनके पद को लोअर ग्रेड में किया गया और ४,०१२ कर्मचारी ऐसे थे जिनकी उन्नति को मार्च, १९६२ तक के लिये रोक लिया गया। ६ हजार लोग गिरफ्तार किये गये और इसके अलावा ६ हजार दूसरे लोग मुअत्तिल किये गये। इस छोटी सी हड़ताल में एक डिपार्टमेंट में, एक विभाग में, इतने लोगों को दंडित किया जाय और उसके बाद भी शासन की ओर से कहा जाय कि हमने कोई सख्ती से काम नहीं लिया ? मैं नहीं जानता कि इसमें कहां तक सच्चाई है लेकिन बहुत ज़िम्मेदार लोगों ने, पोस्ट एंड टेलिग्राफ के कर्मचारियों ने मुझे बताया है कि जब माननीय गृह मंत्री जी से वे मिले तो उन्होंने कहा कि अगर पोस्ट एंड टेलिग्राफ के डाइरेक्ट्रेट के लोग चाहें तो वह लोग उन कर्मचारियों को वापस ले सकते हैं जिनको नौकरी से हटाया गया है। लेकिन जब गृह विभाग की ओर से, गृह मंत्री जी के मंत्रालय की ओर से, खत लिखा गया डाइरेक्ट्रेट को तो

उसमें उल्टी बातें लिखी गईं। जो आश्वासन गृह मंत्री जी ने कर्मचारियों को दिया। वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया गृह मंत्री जी के कार्यालय की ओर से। नतीजा क्या है? आज भी पोस्ट एंड टेलिग्राफ डिपार्टमेंट के ८ लोग नौकरी से निकाले हुए हैं। रेलवे में दूरों की हालत भी ज्यों की त्यों है। बहुत से लोग ऐसे हैं जोकि आज भी मुअत्तिल हैं। १२ लोग आज भी मुअत्तिल हैं जिनमें ईस्टर्न रेलवेमेंस यूनियन के सेक्रेटरी भी हैं। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कोर्ट ने, न्यायालय ने ब्रेकसूर कह करके रिहा कर दिया है लेकिन उनको भी नौकरी में नहीं लिया जाता। मैं नहीं जानता कि जो प्रशासन अपने को प्रजातांत्रिक कहता है, जो प्रशासन यह कहता है कि जुडीशियरी को मान्यता मिलनी चाहिये उस प्रशासन में अगर जुडीशियरी, अगर न्याय विभाग, किसी को निर्दोष समझे तो क्या प्रशासन को यह अधिकार है कि वह उसे दंडित करे। लेकिन यह सब कुछ इस हुकूमत में होता है और उसके बाद भी यह कहा जाता है कि इनके ऊपर कोई सत्ती नहीं की जा रही है। उसके बाद, यह कहा जाता है कि जो लोग विरोधी दलों में हैं, जो लोग इस तरफ बैठते हैं उनको राष्ट्रप्रेम नहीं मालूम। मैं नहीं जानता कि ऐसे लोगों से राष्ट्रप्रेम की शिक्षा कौन लेने जा रहा है। मैं आपके जरिये से इनसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं कर्मचारियों की ओर से कोई भीख मांगने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं तो उन्हें अपने कर्तव्यों की याद दिलाने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हुकूमत इस देश में प्रजातंत्र, जमहूरियत कायम करना चाहती है उस हुकूमत को यह खयाल रखना होगा कि इस देश का छोटे से छोटा कर्मचारी, इस देश का गरीब से गरीब आदमी यह महसूस करे कि उसकी इस देश में उसी तरह की इज्जत है जिस तरह कि किसी पदाधिकारी की है। अगर यह भावना इस देश में नहीं बनती है, अगर छोटे से छोटा आदमी इसके लिये नहीं तैयार होता है तो फिर क्या नतीजा होने वाला

है? आप किसी को राष्ट्रद्रोही कहें लीजिये, आप कह लीजिये कि अदमतशद्द के रास्ते पर वह नहीं चलता लेकिन, श्रीमन्, मैं आपके जरिये से उनको बतलाना चाहता हूं कि वह चलते हैं या न चलते हैं मगर हुकूमत का अगर यही रवैया रहा, यही कार्य करने की प्रणाली रही तो यह हुकूमत अपने कर्मचारियों को, देश के कमजोर लोगों को, देश के गरीब लोगों को यह समझने के लिये मजबूर कर देगी कि जमहूरियत का रास्ता सही रास्ता नहीं है, अदमतशद्द का रास्ता सही नहीं है। प्रजातंत्र और अहिंसा की भावना को अगर बलवती बनाना है तो यह तो हो सकता है कि धनिक धनिक रहे, यह तो हो सकता है कि थोड़े दिनों तक गरीब गरीब रहे और समता का समाज बनने में देर लगे लेकिन अगर व्यवहारों में समता, आपसी आचार-विचार में समता इस देश में नहीं होती तो मैं आपके जरिये से इस सदन में शासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस देश का भविष्य अन्धकार में है और उसी दृष्टि से उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिये मैं कहूंगा कि आम राजनैतिक मनोमालिन्य को छोड़ दीजिये, राजनैतिक विभेदों को छोड़ दीजिये।

(Time bell rings.)

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अगर कोई जीती हुई लड़ाई होती है तो उसके साथ चलते हैं नहीं तो नहीं चलते और इस हड़ताल में भी पहले इसके साथ थे लेकिन जब देखा कि लड़ाई जा रही है तो उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को आगे कर दिया और अपने आप पीछे हट गये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शासन भी वही नहीं कर रहा है। मुझे विश्वास है कि शासन के लोग ही नहीं करेंगे जो कि प्रजातंत्र में विश्वास न रखने वाले लोग करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आपके जरिये से उनसे अनुरोध करूंगा कि उन सारे कर्मचारियों को जो कि नौकरी से हटाये गये हैं बिना किसी दिक्कत के फिर काम पर ले लें।

SHRI M. GOVINDA REDDY (Mysore); Mr. Vice-Chairman, knowing the hon. mover of this Resolution— or at least having heard him—to be a good parliamentarian, I had expected that he would place before the House all sides of this problem. I had expected that he would be no less interested in the efficiency and discipline of the Administration, no less interested in the public welfare than in the interest of the civil services. But I am sorry to observe that he has taken only one view of the matter, namely, the interests of the civil services alone. He has not at all dwelt upon the frightful consequences which a strike of the sort we had the misfortune to have, would have had on the country and the people in general. He has spoken, no doubt, in measured tones unlike the hon. Member who sat to his right in the morning and who raised a shout, wanting to make up by sound what his arguments lacked in force I wish to submit to this House that it would be incorrect and it would be imprudent for this House to accept this Resolution. It would be incorrect, because by accepting this Resolution, we would be laying down something bad in principle, and we would also be accepting a policy which would be suicidal and which would cut at the roots of discipline in the services.

To the merits of reinstatement or otherwise of these persons, I will come later on. I doubt the very propriety of Parliament going into this matter. Now, let us see what has happened. Whether right or wrong—that is a different matter—Departments have taken up the question of these, strikers, those who took part in this strike, those who indulged in disobeying the Ordinance; several cases of sabotage and intimidation, including criminal ones, have been gone into, and the authorities have taken some decision. In some cases the Government have taken the decision and in some cases the Departments have taken the decision. Now, would it be right for Parliament to intervene, to interfere

with these decisions and say: "Well, your decision should go." Suppose we do that, suppose Parliament interfered with the decisions taken by the Government or by the Heads of Departments, tomorrow, with what face and with what authority can the Head of a Department extract service from his subordinates? How can he enforce discipline in the ranks? This is the question which the hon. the mover of the Resolution must see and also the other hon. Members who have spoken in support of the Resolution. In the interest of the services and discipline, is it right that the highest body in the land, Parliament, should intervene and take away from the Heads of Departments and from the Government, the right of taking disciplinary action? That would cut at the very root of efficiency. Therefore, I submit it would not be proper at all for this House to accept this Resolution.

The other question is one of principle. This Resolution involves a principle, namely, whether the services have the right to strike or not. This has been referred to by some of the hon. Members who spoke before me. I would say very humbly that government servants should not have the right to strike. In fact Shri Avinashilingam Chettiar has pointed out the position in the U.S.A. and referred to the Taft-Hartley Act and read out some of the provisions in that Act. There is no State which accords to its servants the right to strike. That is because government servants cannot be deemed to be wage-earners or employees in the ordinary industrial sense of the term. A government servant is not a mere wage-earner. However small a government servant may be, he represents in a measure the institution of government. People do not look to him as to a wage-earner or as a factory labourer. A factory worker may be here today and somewhere else tomorrow. People do not look at a government servant in that way. People look at him as a representative of the institution of government.

Therefore, he is much more than a wage earner, he is much more than a labourer. He represents Government in authority, the sovereignty of the State itself in a measure. He has to consider himself as such and not treat himself as a labourer and that is why he has some privileges and also, more responsibilities devolving on him. A wage-earner today, a worker in a factory or a textile mill, can strike work and can do anything; there is no prohibition. But a Government servant cannot do so. A Government servant is entrusted with the secrets of the Government and he cannot behave in any manner he likes. The Government servants, implicitly or explicitly, take the oath of loyalty to the Constitution and, therefore, it would be insulting the Government servants themselves to treat them as ordinary labourers. Government is also not an ordinary employer in that sense. Government is not an employer in the sense that a factory owner who employs labourers is an employer. So, the ordinary industrial relations of an employee and employer in the matter of the right to strike should not apply here. It is more sacred than that. The relationship between the Government servants and the Government and the Government and the people is more sacred, more sanctified than the relationship between the labourers in a factory and their employer. Sir, Government holds the life of the nation in its hands and Government can administer only through its executive machinery which is the services. So, if the services have a mind and have the right of strike, they can hold the nation to ransom. This is a sacred trust which the Government has distributed to the services and the Government as well as its servants are trustees of this and therefore, Sir, very heavy responsibilities devolve on them. If this body which is holding that sacred trust of the life of the nation, if it goes on strike and paralyses the nation, affects production, industry and trade and causes incalculable harm and hardship, would the public or anybody say that this

188 RS—3.

is right? I can understand that there can be grievances on the part of the Government servants. We have to find out other means, other machinery to redress these, grievances but not give the right to the services to bring the nation to grief. That is a thing which cannot be tolerated. The hon. mover of this Resolution and those who have supported him have claimed that the strike was non-violent where as facts to controvert that position were quoted. It was not a non violent strike. It had resulted in a terrible hardship to the people and perhaps it would have resulted in greater hardship if the people had not co-operated. To our good fortune, the people by and large had sound sense. They did not at all encourage this. Even amongst the Central Government employees themselves by far the larger portion did not encourage the strike and therefore, it could not do much havoc but the little havoc it was able to do is sufficient to open our eyes to reconsider the position whether we should accord this right to the Government servants at all. Sir, I would remind the House of what happened in British Guiana last February. There, Sir, similar conditions prevailed and Government took action. The Prime Minister in his enthusiasm of a progressive ideology took a decision to impose some austerity measures on services as well. Of course, there were other measures also and the services decided to strike work. When the services struck work, do you know what happened? Some people went and dynamited shops and huge fires were started. The water works establishment had closed, had struck work and the electricity department had struck work. The wind was blowing in the direction of the quarters where the very people who fomented this strike resided and they themselves could not help. To their utter regret they found that they could not stop the fire because the water works department had struck work. They themselves suffered and some of them got burnt. This is an instance in point to show that it is a suicidal thing to foment a

[Shri M. Govinda Reddy.] strike, a national strike, on the part of anybody, let alone Government servants. The hon. mover took the name of the late Shri Govind Ballabh Pant, said that he could have been more lenient and that the assurance he held out were not fulfilled. I think Sir, and I think I can say this without being challenged, that it was because of Pandit Govind Ballabh Pant that very liberal measures, were taken. If anybody could surmise an action which was a fitting retaliation to the strike and by the way this strike was run, very severe action should have been called for; but he was a gentleman, as we all know, whose heart was overflowing with the milk of kindness and it was he who softened Government action to a considerable extent, so much so that it enraged many of the people who insisted on the strict enforcement of law and order that the Government should have been so lenient to people who had no second thought for the welfare of the country, who wanted to jeopardise the nation, who even could have promoted chaos in the country. Some figures have been given here and I am giving some figures to show in what liberal measures the Government had softened its action. Action to suspend 27098 people was taken in the beginning but by the end of March last, only 15 remained. In the case of all the others, suspension orders were revoked and they were taken back. There were 2084 dismissals initially when the strike was called off and action was taken but at the end of March last there were only 136 people. Where, is 2084 and where is 136? So many people have been reinstated. A total of 2137 temporary employees were discharged initially but at the end of March this number came down to 61; so many of them were taken back. Departmental proceedings were instituted against 45,945 and at the end of March, Sir, the departmental proceedings stood only in the case of 17 people. Does this not show that Government viewed the matter more liberally? In the cases in which dis-

ciplinary action or punishment has stayed, Government could not intervene because the authorities had gone into each case, the authorities had examined the facts of each case and had come to the conclusion that in such cases punishment should not be lenient and that it should stay. Now, this House should expect that these authorities have discharged their duties properly and truly in relation to the facts before them. Therefore, Sir, when they have deliberately decided—in the face of the instructions of the Government that as far as possible those cases of employees who have not been involved in sabotage, in terrorising and in victimising people, who have not been involved in criminal activities, should be considered liberally, that even criminal proceedings should be withdrawn as far as possible—if the departmental heads have decided that in the case of these 208 people punishment should remain, I think, Sir, this House in its judgement should believe that there must have been some sound reasons for the authorities to have taken that action. If this action is not taken, if even these 208 people are let off, then it would be setting a very bad example before the country and any officer may hereafter with impunity do mischief thinking that later on there would be people who would plead for his retention.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी
चौरडिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है और उस पर जो चर्चा हुई उसको देख कर ऐसा लगा कि माननीय सदस्यों ने, प्रस्तावक महोदय की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा और व्यर्थ में पुरानी बातों की इतनी खींचातानी हुई। जो इस प्रस्ताव की मूल भावना थी और जो करीब करीब काफी सदस्यों के मन में है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए क्या होना चाहिये और क्या नहीं होना चाहिये, इन सब बातों को एक तरफ रख कर जो व्यर्थ की खींचातानी हुई, उससे मुझे बहुत दुःख हुआ। मेरा नम्र निवेदन है कि जो प्रस्ताव की भाषा है

वह बिल्कुल साफ है और जिन कर्मचारियों को हड़ताल के परिणामस्वरूप निकाल दिया गया है उनको फिर से काम पर लगा दिया जाय। इसमें मैंने एक संशोधन दे दिया है और वह इस प्रकार से है "जिन कर्मचारियों को हड़ताल की वजह से डिमोट कर दिया गया, डिग्रेड कर दिया गया, एफिशियेंसी बार से वंचित कर दिया गया है, जिनका इनक्रीमेंट रोक दिया गया है और दूसरे प्रकार से दंडित किया गया है, उन सब को फिर से उनके लाभ वापस कर दिये जायें। परन्तु केरल के एक माननीय सदस्य ने अपने विवृत स्वरूप में बतलाया कि हड़ताल की वजह से, इन कर्मचारियों की वजह से सारे देश में अराजकता फैल गई थी और देश का सारा काम खत्म हो गया था। उन्होंने अपने भाषण के अन्त में यह कहा कि इन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से देश को इतना भयंकर नुकसान हुआ कि ये लोग बिल्कुल क्षमा के योग्य नहीं हैं। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कोई एक छोटा सा झगड़ा होता है तो उसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है। अगर हमारे रेलवे कर्मचारियों और फी० एंड टी० बालों की नीयत खराब होती और वे नुकसान करने पर तुले होते तो सरकार को काफी रुपये की हानि उठानी पड़ती। हमारे मंत्री जी ने बतलाया कि हजारों रुपये का नुकसान इस हड़ताल की वजह से हो गया है। अगर हमारे रेलवे कर्मचारियों की नीयत खराब होती और वे सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते तो वे डोजल इंजनों को आग लगा सकते थे और इसी तरह के दूसरे नुकसान कर सकते थे। आप उनको सजा दे सकते हैं लेकिन नुकसान करने से नहीं रोक सकते। परन्तु उनकी नीयत इस तरह की नहीं थी बल्कि वे सरकार से अपनी साधारण मांग को पूरा करवाना चाहते थे जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल के हथियार को अन्तिम रूप में ग्रहण किया। गवर्नमेंट ने सर्वोद्वेज के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर के समय जो आंकड़े दिये हैं उनको देखकर यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वास्तविक स्थिति

क्या है। सर्वोद्वेज के हेड में सिर्फ २१,६०० का नुकसान दिखाया गया है। यह आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी देशव्यापी हड़ताल हुई और केवल २१,६०० का नुकसान हुआ। हमारे माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि सारे देश में इस हड़ताल की वजह से अराजकता फैल गई और सारा देश नष्ट-भ्रष्ट हो गया बिल्कुल गलत बात है। उन्हें इस तरह की गलत बातें नहीं कहनी चाहिये क्योंकि हम जनता के हित की भावना को लेकर यहां पर आये हैं और इस तरह की गलत बयानी करके हम जग दूर जाते हैं। अगर हम इस नुकसान को दूसरे एंगल से देखें तो हम यह पायेंगे कि जितना नुकसान हड़ताल की वजह से हुआ है वह कांग्रेस के शासन की वजह से हुआ है। उसने कर्मचारियों की मांगों का ठीक समय पर अनुमान नहीं लगाया और न ही उसका कोई इलाज किया। भाषणों के दौरान कई आंकड़े दिये गये और लम्बी चौड़ी बातें कही गईं जो कि बिल्कुल गलत हैं। एक ओर तो हम कर्मचारियों की तनखा बढ़ाते हैं और दूसरी ओर उन्हें लिमिटेड एम्पाउन्ट देते हैं। इसके साथ ही साथ हम दूसरी ओर करोड़ों रुपये के नोट छापते हैं। हम अपने स्टैलिंग बैलेंस को कम करते और करेंसी को फैलाते हैं और इस तरह से उन रुपये की परचेजिंग पावर कम करते हैं। इस तरह से जो सरकारी कर्मचारी एक फिक्सड तनखा पाते हैं उनकी कठिनाइयां करेंसी के फैलाव से बढ़ जाती हैं और आप उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं और करेंसी को फैलाते ही चले जाते हैं। सन् १९५५-५६ से लेकर जनवरी सन् १९६० तक ४२० करोड़ रुपये की करेंसी की वृद्धि हमारे शासन द्वारा की गई है। हमारा जो स्टैलिंग बैलेंस था उसमें ५२५ करोड़ रुपये की कमी हो गई है और खूबी यह है कि वह भी सरकुलेशन में आ गया है। एक तरफ तो आप इस तरह की स्थिति निर्माण करते हैं और दूसरी तरफ जो रुपये

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया]
आप उन्हें देते हैं उसकी परचेजिंग पावर
कम कर देते हैं। एक तरफ तो आप यह नारा
लगाते हैं कि हम देश में सोशल वेलफेयर
स्थापित करना चाहते हैं, देश में जो काम
करने वाले लोग हैं उनकी रक्षा करना चाहते
हैं और दूसरी ओर इस तरह की कठिनाइयां
पैदा करते हैं जिससे उनको लाभ न पहुंचे।
जब ये लोग अपनी मांग सरकार के सामने
रखते हैं तो उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता
है और यह कहा जाता है कि अगर गलती
करोगे तो सजा दी जायेगी। जिनके हाथ
में कर्मचारियों का भार है, जो पिता तुल्य
अपने को शासक मानकर चलना चाहते हैं
और उनकी पुत्र के प्रति जो भावना होनी
चाहिये, उस भावना को साथ रखकर काम
नहीं करते हैं तो माननीय उपसभाध्यक्ष
महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरह
से पुत्र को शिकायत करने का अधिकार है
उसी तरीके से उन्होंने किया। सरकारी
कर्मचारियों ने शान्तिपूर्ण तरीके से अपने
असंतोष को जिस तरह से प्रकट किया उसके
बावजूद भी हमारी सरकार ने यह कहा
कि ये लोग बागी हैं और देशद्रोही हैं।
सरकारी कर्मचारियों ने सरकार को पहले
सूचना दे दी थी कि हमारी ये ये मांगें हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पे कमिशन
के संबंध में यह घोषणा की है कि इसको एवाड
के रूप में मान लिया जायेगा लेकिन उसको
आज तक पूर्ण रूप से एवाड नहीं माना गया।
इस संबंध में कई बातें हैं और मैं डिटेल् में जाना
नहीं चाहता हूं। मैं केवल यह निवेदन करना
चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों की मांग
चाहे उचित थी या अनुचित थी लेकिन
करेंसी का फैलाव जिस तरह से फैल गया
है, टेक्सेज का भार जिस तरह से बढ़ गया
है इन दो पाटों के बीच में हमारे सरकारी
कर्मचारी पिस गये हैं। उनको इससे कोई
राहत नहीं दी गई और न ही उनकी मदद
करने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था
की गई। उन्होंने आप से मांग की कि हमारा

पेट भरिये, हमारी जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर
कीजिये। हमारी कुछ कठिनाइयां हैं उन्हें
आप मिटाइये। उन्होंने प्रधान मंत्री जी से
यह मांग की कि हमारी बात सुन लीजिये
और फिर आप जैसा चाहे वसा कर लीजिये।
अगर आप पिता तुल्य बनना चाहते हैं तो
आप अपने लड़के की बातें सुनिये। अगर आप
का लड़का नालायक है तो आप उसे घर
से निकाल दीजिये। इसके साथ ही
आप यह भी चाहते हैं कि पुत्र पिता
के प्रति उपेक्षा न करे, यह न्यायसंगत बात
नहीं लगती है। तो मेरा नम्र निवेदन है जो
जिम्मेदारों हमारे शासन का थी, उसके
निर्वाह करने में हमारा शासन सफलीभूत
नहीं हुआ और उसके परिणाम स्वरूप करोड़ों
रुपये की क्षति हुई। उसकी जिम्मेदारी थोड़ी
कर्मचारियों पर है और ज्यादा शासन पर है
जिसकी वजह से यह चीज हुई। अगर आप
आत्मशोधन करेंगे तो यह पायेंगे कि जो यह
करोड़ों रुपये की क्षति हुई है वह केवल शासन
की वजह से हुई है। अगर आप इस चीज
का प्रायश्चित्त करना चाहते हैं—जल्दतः इस
बात की है कि प्रायश्चित्त करें क्योंकि इन
कर्मचारियों द्वारा तो केवल २१ हजार रुपये
का नुकसान हुआ है मगर आपकी लापरवाही
की वजह है, आपकी उपेक्षा की वजह से देश
का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है जिसके
लिये आपको जरूर प्रायश्चित्त करना चाहिये।
मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से काम करें
और प्रायश्चित्त करने से पहले खुद अपने
को सजा दें। मैं सजा देने की क्षमता नहीं
रखता हूं। मैं तो जो वास्तविक बात है वह
उन के सामने रखना चाहता हूं। जो लोग
बापू के आदर्श पर चलना चाहते हैं
उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये तब ही वे
उनके पदचिह्न पर चलेंगे। अगर वे इस तरह
का कष्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

जहां तक हमारे कर्मचारियों का पक्ष है
वह बिल्कुल निर्विवाद साबित हो चुका है।
हमारे कर्मचारियों के खिलाफ यह आप
लगाया जा रहा है कि उन्होंने देशद्रोह का

काम किया है, तोड़ फोड़ की कार्यवाही में भाग लिया है जिसकी वजह से उन्हें पीना-लाइज किया जा रहा है और जलौल किया जा रहा है। अब प्रार्थना यह है कि इन बेचारों जिनको इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है और सब बाँटें हो रहे हैं, उन्हें फिर से नौकरी में लवा दिया जाय। जिनको डिमोट कर दिया गया है उन्हें नौकरी में वापस उनके स्थान में कर दिया जाय। उनकी माँगे वाजिब थीं इस लिये बाद में उनका माँगे स्वीकार की गई। गलती आप करें, सजा उन्हें दें, यह बात उचित नहीं लगती है। हमारे श्री नवाबसिंह जी ने जो एक 3 P.M. उदाहरण दिया कि आर्डिनेंस बाद में निकला, भाषण उसके पहले दिया, सजा बाद में दे दी, वह अन्धेर नगरी चौपट राज वाला किस्सा है कि तू ने गुनाह नहीं किया, तेरे बाप ने गुनाह किया, इसलिये तुझे सजा दे देता हूँ। तू ने आज गुनाह नहीं किया और आर्डिनेंस आज निकला तो क्या हुआ। तू ने अगर गुनाह नहीं किया, लेकिन आर्डिनेंस आज निकला, तो इसी बहाने तुझे दूढ़ दूढ़ कर पेनेलाइज करना चाहते हैं। यह तो अन्धेर नगरी चौपट राज सरीखी घटना प्रिय नहीं लगती। यह ठीक है कि हमारा शासन लिबरल रहा। लिबरल होना बुरा नहीं, क्षमा करना बुरा नहीं, क्षमा वीरता का लक्षण है। आपको लड़ना है तो चीन के मोर्चे पर लड़िये और खूब बहादुरी बताइये। उसे हम मना नहीं करते। आपको अगर लड़ना है तो पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़िये। तो हमको अगर अपनी बहादुरी का परिचय देना है तो उसके लिये बहुत से क्षेत्र हैं। हम अपने बच्चों पर, हम अपने नौकरों पर, हम अपने कर्मचारियों पर सत्ता का—सदुपयोग शब्द तो मैं नहीं कहता—दुरुपयोग करें तो यह कभी भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि आप जरा शान्तिपूर्वक इस प्रकरण को सोचें जिस पर सदन में इतनी खींचातानी हुई और जिसकी

काफ़ी चर्चा हुई। उसको हमारे चेदिटियार साहब ने इतना विकृत स्वरूप दिया कि मैं वहाँ आश्चर्य में पड़ गया कि अगर उस जमाने में किसी अंग्रेज़ का भाषण सुनता तो सम्भवतः वह भी इतना विकृत स्वरूप नहीं देता। उन्होंने आई० एन० टी० यू० सी० की रिपोर्ट पढ़ी।

श्री इयाल दास कुरें (मध्य प्रदेश) :
उन्होंने ज्वलन्त उदाहरण रखे।

श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : आई० एन० टी० यू० सी० की किताब से मैं भी ज्वलन्त उदाहरण दे रहा हूँ जो स्वयं आपकी सरकार ने प्रश्नों के उत्तर में बताया था। २१६०० रुपये से एक पाई या एक नया पैसा भी अधिक नुकसान किसी कर्मचारी ने कर दिया हो तो बतला दीजिये। आप उसको अपनी बात सुनाने का मौका भी नहीं देते हैं। आप पिता बनने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन जब पुत्र कहता है कि पिता जी सुनिये तो सही, तो आप सुनते नहीं हैं। उसके बाद अगर वह कुछ करता है तो उसके विरोध स्वरूप आप उसको सजा दे देते हैं। तो गुनाह उन कर्मचारियों ने नहीं किया है। गुनाह आप लोगों ने किया है जिन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। करोड़ों का नुकसान उन लोगों ने किया है जिन्होंने सुना नहीं। इसलिये सजा के भागो वे हैं जिन्होंने उनकी सुनवाई नहीं की। इस खींचातानी से कोई लाभ नहीं है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि आपने जैसा कोनियंट व्यु अभी तक लया है और एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो भाव होना चाहिये, उसके अनुसार मैं चाहता हूँ कि जो ऐसे पुत्र आपके रह गये हैं, उनको भी अपना अधिकार मिलना चाहिये। जिन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, उनकी भावना के बस आकर मैं यह कहूँगा कि यह २१ हजार का नुकसान कोई अधिक नहीं है। जो छोटे छोटे आन्दोलन होते हैं उनमें भी भावनाओं में बड़ा अंतर, मास मेंटालिटी जिस को कहते हैं उसको आन्दोलनों में भाग लेने वाले

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया]
सदस्य अन्धरी तरह जानते हैं, उस मास मेंटा-
लिटी के परिणामस्वरूप लाखों और करोड़ों
रुपये का नुकसान हो जाता है और कुछ पता
नहीं लगता। कराची में अपने मकान में पन्थर
फेंक करके अपने मकान को बरबाद कर दिया।
कितनी जगह ऐसे उदाहरण हैं। पाटली श्री
रामालु का ज़रा सा उदाहरण हुआ जिसमें
लाखों रुपये साफ़ हो गये। यह देशव्यापी
इतनी बड़ी हड़ताल हुई और इसमें केवल इतना
नुकसान हुआ। फिर भी मक्खी को मल मल
कर के भैंसा बना दिया और इतना विकृत
स्वरूप बना दिया कि समझ में आने वाली
बात नहीं है।

इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि अटल
बिहारी वाजपेयी जो ने जो प्रस्ताव रखा है
उसको स्वीकार करने का काट कैं। साथ ही
उसमें जो मैंने संशोधन दिया है कि जो डिमांड
हो गये हैं, उनको प्रोमोट करके अपने पुराने
स्थान पर रखा जाय, वह भी कृपा करके
स्वीकार किया जाय। अन्त में मैं फिर मंत्री
महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे शान्तिपूर्वक,
गम्भीरतापूर्वक एक पिता का पुत्र के प्रति
क्या कर्तव्य होता है, उसको ध्यान में रख कर
उसके अनुसार उन लोगों को लाभ देने की
कृपा करें।

श्री शीलभद्र याजी : माननीय वाइस
चेयरमैन महोदय, प्रस्तावक महोदय ने जो
प्रस्ताव रखा है उसके द्वारा, मैं समझता हूं
कि जिनके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है,
उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। हमारे
गृह मंत्री जी ने यह ऐलान किया था कि
उनके साथ हम प्यार के साथ बर्ताव करेंगे
और हमारे प्रस्तावक महोदय ने भी अपनी
स्पीच में यह कहा कि जिन लोगों ने वायलेंस
किया है, हिंसा की है, सेबोटेज किया है,
उनको न लिया जाय, लेकिन यह प्रस्ताव रख
करके उन्होंने इसको इतना व्यापक कर दिया
है कि न इसको सरकार मानने जा रही है
और न हाउस ही मानने जा रहा है। अब
अगर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया जाता है तो

इसके परिणामस्वरूप जो १३६ मुलाजिम अभी
रह गये हैं उनके लिये उन्होंने एक बहुत
बड़ी संकट की घड़ी उपस्थित कर दी है।
जिस तरह से उन्होंने स्पीच दी, उस तरह से
यदि वे अपना प्रस्ताव रखते तो ज्यादा
उचित होता। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया
कि २२ लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी
हैं, इतने लाख लोग इसमें शामिल हुए,
इतने हजार पर ऐक्शन हुआ और अब १३६
पर आ गये हैं। इसलिये इस पर विशेष वाद-
विवाद की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन
प्रस्तावक महोदय ने यह प्रस्ताव रख दिया
और इसका एक ऐसे आदमी से समर्थन प्राप्त
हुआ कि तमाम इधर उधर की बातें आ गईं।
इस स्ट्राइक का सारे देशभक्त लोग शुरू से ही
विरोध करते आये हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने
भी कहा था कि जब चीन वाले हमारी सीमा
पर मौजूद हैं और आसाम में दुर्घटनाएं हो
रही हैं, तो ऐसी दशा में हड़ताल करना उचित
नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि हम
उनकी मांगें स्वीकार करेंगे। उसके बाद जो
तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विरोधी
दल के लोग हैं, उन्होंने यह सोचा कि जनता
तो कभी उनको गद्दी देगी नहीं, इसलिए
गद्दी पर बैठने के लिए क्यों न एक बड़ी भारी
ग्राम हड़ताल करा दी जाय। उस समय इन
लोगों में अजीब गठबन्धन हुए। कहां
पी० एस० पी०, कहां कम्युनिस्ट पार्टी,
कहां जन संघ, कहां हिन्दू महा सभा, फिर
भी सब में गठबन्धन हो गया।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया :
कहां केरल, कहां मुस्लिम लीग, यह भी
कह दीजिये।

श्री शीलभद्र याजी : आप बैठिये,
मैं आपको समझा दूंगा। हमारे प्रधान मंत्री
जी ने कह भी दिया कि हड़ताल नहीं होनी
चाहिये और हड़ताल गैर कानूनी घोषित भी
कर दी गई, फिर भी हमारी तमाम विरोधी
पार्टियों ने हड़ताल कराई। हम नेता जी के
पीछे चलने वाले हैं। नेता जी ने कहा था

कि देश में जो शासक पार्टी हो, वह यदि समाजवाद ग्रहण करती है, तो देश में कोई खास स्ट्राइक नहीं हो सकती, कोई वर्ग संघर्ष नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त एक यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते और इस पार्लियामेंट का मेम्बर होने के नाते मैं बराबर इस विचार को रखता आ रहा हूँ कि हड़तालों को सदा के लिये गैर-कानूनी घोषित कर दिया जाना चाहिये। जो पार्टी समाजवाद स्थापित करना चाहती है, वह यही चाहेगी। हड़ताल कराना उसी पार्टी का काम हो सकता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ थी, कभी मुस्लिम लीग के साथ थी और जिसने अब देशद्रोही का नाम ले लिया है। मेरा कभी यह तरीका नहीं रहा है कि मैं यहां कुछ कहूं और बाहर कुछ कहूं। जब मैं ठीक समझता हूँ तो अपनी सरकार को भी मुना देता हूँ। जब स्ट्राइक हुई थी तब भी मैंने कहा था कि सरकार का बड़ा लीनियेंट ऐक्शन रहा, जो यूनियनों स्ट्राइक कराने वाली हैं, उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिये। लेकिन दुःख यह है कि हमारी बात सरकार भी नहीं सुनती है और कमजोरी दिखलाती है। कहा गया है कि २१ हजार रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन वास्तव में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। रेलवे में जिस तरह से हड़ताल हुई और जिस तरह से गाड़ियां बन्द रहीं, उसके यदि आंकड़े निकाले जायें तो मालूम होगा कि करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। नुकसान की बात जाने दीजिये। जब कि हमारा दुश्मन चीन हमारी सरहदों पर बैठा हुआ है, जब कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम इधर उधर की बातें होती रहती हैं, ऐसे समय में हड़ताल कराना कहां तक उचित कहा जा सकता है? वास्तव में जो अपने को समाजवादी कहते हैं, जो अपने को देशप्रेमी कहते हैं, उन्होंने जुलाई, १९६० में हड़ताल करके देशद्रोहियों का काम किया। इसी लिये प्राइम मिनिस्टर ने उस समय कहा था कि ये ऐंटी नेशनल स्ट्राइक है, यह राष्ट्र-विरोधी स्ट्राइक है।

जो जनता जनार्दन है, जो रेलवे कर्मचारी हैं, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, उन्होंने यदि उस समय देश-भक्ति से कार्य नहीं किया होता, तो पता नहीं क्या होता। हम लोग इस पार्लियामेंट में बैठने पाते या नहीं बैठने पाते, सरकार रहती या नहीं रहती, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होता। वह एक राजनैतिक स्ट्राइक थी। मैं भी एक रेलवे यूनियन का सभापति हूँ और मैं जानता हूँ कि उस जमाने में पी० एस० पी० और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अपने भाषणों में क्या कहते थे। वे कहते थे कि यदि यह सरकार खत्म हो जाती है और हमारे आदमी सरकार में आ जाते हैं तो हम तुम्हारी तनख्वाह चार सौ रुपये महोना कर देंगे। तमाम राजनीतिक नेताओं की ऐसी ही स्पीचेज होती थीं। वे बराबर इसी तरह के भाषण देते थे। इसके बाद गवर्नमेंट ने भी कुछ कड़ाई की। देश की जनता ने भी साथ दिया और खास करके जो हमारी नेशनल फेडरेशन आफ रेलवेज है उसने भी देशभक्ति की बात की और सरकार को सपोर्ट किया। आई० एन० टी० यू० सी० ने भी सपोर्ट दिया और खास करके नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे इम्प्लोईज ने दिया। ११ लाख रेलवे के कर्मचारी हैं उनको बताया कि यह राजनैतिक हड़ताल है और इसमें राजनैतिक पार्टी के लोग हैं, इससे बहुत बुराई होने वाली है और इसीलिये जो तमाम इस यूनियन के कर्मचारी थे उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और यह जो स्वप्न था एक राज्य स्थापित करने का और जो एक राजनैतिक उद्देश्य था उन सब पर तुषारापात हुआ और इसी वजह से एक रोज भी हड़ताल नहीं चल सकी।

अब प्राइम मिनिस्टर के कहने पर भी, दूसरे लोगों के मना करने पर भी और स्ट्राइक को इल्लिगल करने पर भी लाखों लोग स्ट्राइक में शामिल हुए लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जिन लोगों ने स्ट्राइक का नेतृत्व किया,—जो पोलिटिकल पार्टी के

[श्री शीलभद्र याजी]

लीडर स्ट्राइक कराने वाले थे और जिनके लिये हम चाहते थे कि उनको लम्बी सजा देनी चाहिये, उनको जेल में रखना चाहिये, उनको नजरबन्द रखना चाहिये— उनके ऊपर कोई कड़ाई नहीं की गई। उधर स्ट्राइक का नोटिस भी हो रहा है और इधर पार्लियामेंट में कामरेड भूपेश गुप्त की इसके मुताल्लिक स्पीच भी हो रही है, यह हमने देखा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अरेस्ट भी हुए तो सब से पहले छुटे। हम लोग जो कि इस विचार को रखने वाले थे कि जिन केन्द्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था उन पर यदि सरकार कोई कड़ाई करती है तो वह ठीक नहीं है, उनको यह देख कर दुःख हुआ कि जो गुनहगार थे और जिनको लम्बी सजा देनी चाहिये थी उन पर भी कोई कड़ाई नहीं की गई। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार, हमारे गृह-मंत्री जी मजबूत हैं लेकिन मेरे ख्याल से वह बहुत कमजोर हैं। अगर हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो ये जो देश-विरोधी दोस्त हैं उनके खिलाफ कड़ाई करनी होगी। अगर उनके ऊपर कड़ाई नहीं होगी तो मुल्क में तरह तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपने दया का बर्ताव उन पोलिटिकल लीडरों के साथ किया। सरकारी कर्मचारियों का क्या कसूर था? वे तो बेचारे उनके नारों में फंस गये लेकिन आपने उन लीडरों को जल में भी रखा तो आराम से रखा और फिर छोड़ दिया। कई लाख लोग हड़ताल में शामिल हुए और उनके साथ दया का बर्ताव करने के बाद अब आप १३६ लोगों पर आ गये हैं, लेकिन ये १३६ लोग सैबोटेज करने वाले हैं, वायलेस करने वाले हैं और उनको भी यदि आप छोड़ देते हैं तो ये लोग जो आइंदा के लिये मंगूबा बांधे हुए हैं कि कभी कभी स्ट्राइक करेंगे उनका इरादा पूरा हो सकता है। ६। लये उनके साथ तो कोई नर्मी नहीं नी चाहिये। लेकिन, हम यह भी जानते हैं, मैं रेलवे यूनियन का प्रेसिडेण्ट हूँ, जो

हमारी विरोधी यूनियन है, जो कि स्ट्राइक करा रही थी उससे हमारे लोग लड़ते थे— पुलिस इस बात को जानती है, पुलिस की इस बारे में रिपोर्ट है कि ये लोग स्ट्राइक के खिलाफ थे और सरकार को मदद करते थे, परन्तु अब जो रेलवे के बड़े-बड़े आफिशियल्स हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी और पी० एस० पी० के सिम्पेथाइजर्स हैं, जिन लोगों ने स्ट्राइक में मदद दी, वे अब हमारे लोगों पर ऐक्शन लेते हैं। हमारे लोगों की नौकरी गई, उनका सस्पेंशन हुआ और जो दोषी थे उन पर ऐक्शन नहीं हुआ। अब भी हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे केसेज हैं। हमारे बाजपेयी जी ने भी इस बारे में कहा कि हम जानते हैं। रांची में एकाउंटेंट जनरल के आफिस में पीसफुल स्ट्राइक थी और वहां के बलभद्र झा और हरी चौबे हैं जो कि यूनियन के लीडर हैं, किसी पार्टी से उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है लेकिन सरकारी कार्यवाही भी अजीबोगरीब है कि इतना शांत रहने पर भी इसके बाद इन लोगों का कम्पलसरी रिटायरमेंट हुआ। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि किसी पार्टी के नहीं हैं, न इनकी किसी पार्टी के प्रति वफादारी है और न सम्बन्ध है लेकिन वे जो सरकारी आफिशियल्स हैं, उनकी जो मनोवृत्ति है, वे जो फेलोट्रेवलर्स हैं, उनकी वजह से इन लोगों की नौकरी जाती है और कम्पलसरी रिटायरमेंट होता है। ये आफिशियल्स हमारी सरकार को भी सैबोटेज करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। रेलवे में मैंने देखा कि हमारी यूनियन के लोगों ने बड़ी हिम्मत करके उनका सामना किया, उनको घर से पाखाना जाने के लिये निकलना कठिन था लेकिन उन्होंने सब बातों का बड़ी मुसीबतों के साथ मुकाबिला किया, पर जब ऐक्शन लेने की बारी आई तो सस्पेंशन पहले उनका ही हुआ जिन लोगों ने कि मुसीबत उठाई थी। रेलवे के अधिकांश कर्मचारियों ने नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे इम्प्लोईज का साथ दिया, दिलेरी से और

देशभक्ति से साथ दिया और उसके साथ बढ़े, लेकिन उनको इस काम का पुरस्कार नहीं मिला बल्कि उनको सस्पेंशन मिला। बहुत लोगों को सस्पेंड किया गया। हमारे होम डिपार्टमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट लिखी थी कि ये तो हमारे साथ काम करते थे फिर भी सस्पेंशन होता है। कहीं कहीं तो जेनरल मैनेजर ने भी कुछ नहीं किया और उनकी भी नौकरी खाली। तो इस तरह का कांड हुआ है। इस तरह की बात हमने मंत्रिमंडल को भी बताई और कहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब जो १३६ रह गये हैं—आपने और सब से दया का बर्ताव किया—उनके लिये मैं आपको आगाह करता हूँ, मैं एलेक्शन की बात नहीं करता हूँ लेकिन हिन्दुस्तान में इस तरह के तत्व हैं जो कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के बीच में भी काम करते हैं, वे तरह तरह के नाममात्र के बहाने पर सैबोटेज करेंगे और फिर स्ट्राइक की बात करेंगे। यह मेरी निश्चित राय है। आपने कहा था कि जितने केन्द्रीय कर्मचारी हैं उनके बीच में स्ट्राइक नहीं होगी और आप उसको इललीगल करेंगे, लेकिन उस चीज को आपने खटाई में डाल दिया। यदि आप चाहते हैं कि देश में समाजवाद की स्थापना हो और देश में गड़बड़ी न होने पाये तो इसके लिये प्रबन्ध करना होगा। देश के जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान है, चीन है, वह आपके अगल-बगल में बैठे हुए हैं और देश में भी बहुत से दुश्मन बैठे हुए हैं। अगर आप इनसे मुकाबिला करना चाहते हैं तो फिर स्ट्राइक को इललीगल घोषित करना पड़ेगा। सब लोगों ने यह भी कहा था कि एक पर्सनल ट्राइब्यूनल बनना चाहिये जो कि मुलाजिमों और अधिकारियों के बीच में जितनी बातें आँखों से उनका जल्दी से जल्दी फैसला करेगा। इस तरह के पर्सनल ट्राइब्यूनल के बनाने की जरूरत है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो स्ट्राइक हुई थी वह नाकामयाब हुई, ये लोग बुरी तरह से मारे गये, पीटे गये; चाहें वे इस पार्टी

के हों या उस पार्टी के हों क्योंकि जनता सरकार के साथ थी, कांग्रेस के साथ थी, देशभक्तों के साथ थी। तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि २२ लाख हैं, उनमें से अधिकांश देशभक्त हैं और इसीलिये उन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। यदि कुछ लोग भी इनके साथ हो जाते तो यह सरकार अपंगु हो जाती। लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, श्री विमलकुमार जी ने कहा कि इसको बड़ा बनाया जा रहा है लेकिन जेनरल स्ट्राइक की जो दावत दी गई थी वह अगर कामयाब हो जाती तो फिर मुल्क में क्या होता? क्या क्या नहीं होता, एनारकी नहीं होती? क्या क्या नहीं होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं।

श्री बी० एम० चौरङ्गिया : १९४२ के आन्दोलन को सफल होने में तो कठिनाई पड़ी थी और इसमें क्या होता, यह तो जरा सोचने की बात थी।

श्री शीलभद्र याजी : तो जो १३६ लोग हैं, जिन लोगों ने सैबोटेज किया, वायलेंस किया उनको कभी नौकरी नहीं मिलनी चाहिये। यह प्रस्ताव बहुत व्यापक है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इन लोगों के साथ किसी प्रकार की लीनियेंसी नहीं होनी चाहिये लेकिन जो जी के साथ घुन पिस रहे हैं उनको जल्दी ही नौकरी में लेना चाहिये। आपको देखना चाहिये, आपके जो आफिशियल्स हैं उनको देखना चाहिये और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखना चाहिये कि किस तरह से कहां क्या अन्याय हुआ है।

यह जो वाजपेयी जी का प्रस्ताव है यह जिस रूप में है वह अधूरा प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव को मानने से जो सैबोटेज करने वाले हैं, वायलेंस करने वाले हैं उनसे लिये दरवाजा खुल जायगा इसलिये मैं सरकार को राय दूंगा कि इस प्रस्ताव को वह ठुकरा दे, इसका वह माने नहीं लेकिन इसके साथ ही साथ यह कहूंगा कि जो लोग ऐसे हैं जो कि जी के साथ घुन की तरह पिस रहे हैं, उनके साथ लीनियेंसी

[श्री शीलभद्र याजी]

दिखाना चाहिये। जब हम लाखों को भूल गये, हजारों को भूल गये तो ये जो थोड़े से लोग हैं—बाहेर वे एकाउंटेंट जनरल के आफिस में हों या रेलवे में हों—उनके साथ दया का बर्ताव जरूर होना चाहिये। इन शब्दों के साथ, इस प्रस्ताव पर जो मेरा मत था वह मैंने प्रस्ताव महोदय से भी कहा और अपनी सरकार से भी कहा और मैं समझता हूँ कि इस ह्राउम में जो एंटी नेशनल हैं उनकी बात तो जाने दीजिये, लेकिन जो देशभक्ति रखने वाले हैं उनको तो सोच-समझ कर कदम उठाना चाहिये। जय हिन्द।

श्री एम० गौरे : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन में जो बहस मैंने सुनी है उससे तो ऐसा मालूम होता है कि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी में लेने की बात तो अलग रही लेकिन कुछ पार्टियों पर चुन चुन कर के गालियों की बीछार करने या उनको अराष्ट्रीय कहने का एक मौका मिल गया है। मैं सब से पहले जो आरोप कुछ पार्टियों के ऊपर यहां पर लगाये गये हैं, उस बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

एक तो कम्युनिस्ट पार्टी को कहा है कि अराष्ट्रीय है और जनसंघ को कहा है कि कम्यूनल है। लेकिन मुझे ऐसा मालूम हुआ है और अभी जो आम चुनाव हो गये हैं उसके दौरान भी यह बात साबित हुई है कि देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जो शासन कर रही है, उससे ज्यादा कम्यूनल पार्टी और कोई नहीं है और अराष्ट्रीय पार्टी की जो बात कही गई है उसके बारे में भी हम सब एक राय पर पहुंच गये हैं कि शायद देश के लिये अगर कोई पार्टी सब से ज्यादा अराष्ट्रीय है, तो वह कांग्रेस पार्टी के सिवाय और कोई नहीं है। उसके बारे में मैं यहां भी बताऊंगा . . .

श्री शीलभद्र याजी : उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : क्या किया अभी तक आपने ?

श्री एम० गौरे : मैं उसका कारण भी बताऊंगा। जो पार्टी देश में शासन कर रही है यदि वह हमारी सोमा को रक्षा नहीं कर पाती, यदि वह हमारे देश में किसी इलाके को चीन या और किसी के कब्जे में रख छोड़ती है, वह कितनी गद्दार या अराष्ट्रीय है? वह खुद अराष्ट्रीय है क्योंकि राष्ट्र के साथ उसने गद्दारी की है। तो जिस पार्टी ने अपने देश का हिस्सा और किसी के जिम्मे किया हो वह हम में से किसी को बताये कि तुम अराष्ट्रीय हो तो इसको मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं। अराष्ट्रीय का क्या मतलब होता है? सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर दी और उनका जिन्होंने नेतृत्व किया उनसे कहना कि वे अराष्ट्रीय है और जो हड़ताल हुई वह अराष्ट्रीय है, यह बिल्कुल झूठ बात है क्योंकि आखिर यह हड़ताल किसके लिये हुई, किसकी मांगों को लेकर हुई? अगर देश में गरीबी फैली हुई है, देश में दामों की लूट मची हुई है और देश में जो असली आमदनी है और दामों की बढ़ती हुई दौड़ है, उसका कोई जोड़ नहीं तो फिर अगर कोई यह मांग करे कि हमारे वेतन में वृद्धि हो, और हम उसके बारे में यह कह दें कि अराष्ट्रीय है तो यह बिल्कुल बचकनापन है। आखिर एक चीज की हद होती है, कौन सी चीज राष्ट्रीय है और कौन सी अराष्ट्रीय है उसकी हद होती है। हर चीज को लेकर कह दें कि कम्युनिस्ट ने नेतृत्व किया है या प्रजा सोशलिस्ट ने नेतृत्व किया है इसलिये अराष्ट्रीय है, यह देश की गद्दारी है, देशद्रोह है और बिल्कुल बचकनापन है। इस तरह की चीजें इस सदन में नहीं कही जानी चाहियें।

मैं तो उन बिनो को याद दिलाऊंगा जिन दिनों में यह हड़ताल हुई थी। हड़ताल रात के समय शुरू होने वाली थी। जो नेता थे, वे सब यह आशा करते थे कि भाज सरकार कोई

न कोई शांतिपूर्ण हल निकाल लगे, लेकिन हमको तो पूरा यकीन था कि इसका कोई शांतिपूर्ण हल नहीं निकालने वाला है; क्योंकि हम इस गवर्नमेंट की नीयत को जानते हैं और इन सरकार को नीति को भी। इसलिये हम कोई आशा नहीं रखते थे। मैंने तो पहले से कहा था कि यह हड़ताल हो कर रहेगी लेकिन वायद आखिरी मोर्चे पर कुछ नेता लोग समझौता करके यह हड़ताल नहीं करायेंगे। लेकिन फिर भी जो हड़ताली नेता थे वे लोग सब यहो आशा करते थे कि किसी न किसी तरह से समझौता हो जायेगा और ऐसे नेता लोग आखिरी दम तक समझौते के लिये उत्सुक थे। लेकिन समझौता नहीं हो पाया और हड़ताल हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, यहां लोगों ने यह कह दिया कि यह एक राजनैतिक विद्रोह था। अरे, हम तो खुश होते अगर राजनैतिक विद्रोह होता इस देश में। जहां इस तरह की सरकार हो, जहां लोगों को खाना न मिले, कपड़ा न मिले और फिर भी यह कहा जाये कि यह विद्रोह है। विद्रोह अगर होता तो खुशी की बात थी। कम से कम सरकार को अकल तो आती कि ये सब जितनी नीतियां चल रही हैं वे सब शलत हैं और उनको सुधार लें। लेकिन वह राजनैतिक विद्रोह क्या था? उन लोगों ने हड़ताल की और उसमें जो कुछ हुआ वह आपने देख ही लिया। उसको इतनी जोर से दबाया गया और कुचल दिया गया कि उस तानाशाही का कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि वहां पर बहुत रहम दिखाया गया, लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा बर्ताव किया गया क्योंकि मैं देख चुका हूं, मिकन्दरावाद लोको वर्क में जब पुलिस वहां पर गई तो उसने रेलवे वर्कर्स को उनके क्वार्टर से बाहर धसीट कर उनकी औरतों को मारा-पीटा और १०० से ज्यादा लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया। यह कहना कि बड़ा रहम दिखाया गया, यह कितना सही, कितना झूठ है, इसकी सच्चाई आपको मालूम करनी है तो पूरी रिपोर्ट देखें तब आपको पता चलेगा।

हर जगह पुलिस का जुल्म रहा। आपको सुबह सुनाया गया कि पांच लोगों की मौत भी हुई। और यह कह देना कि लोगों ने अराष्ट्रीय काम किया और देश में बलवा पैदा करने की कोशिश की है, यह सरासरी शब्द है। बलवा पैदा करने वाला वह होता है जो पहले से अपना आयुध ठीक करके बलवा करता है। हड़ताल करने वालों के पास क्या था? कुछ नहीं था। उन लोगों ने हड़ताल की तो पूरी सरकार का जितना आयुध और पुलिस थी वह सब उनके पास थी और सरकार ने बिल्कुल झूठा प्रचार स्ट्राइक के दिनों में चलाया। आल इंडिया रेडियो से हम सुनते थे कि पेरम्बूर वर्कशाप में चंद लोग बाहर निकले, यहां तो कोई हड़ताल नहीं हुई जब कि वहां पेरम्बूर वर्कशाप बंद पड़ा था। इस तरह का झूठा प्रचार सरकारी यंत्रों द्वारा किया गया। खैर जो कुछ हुआ हुआ, सरकार ने तो बहुत ही बुरा किया। लेकिन अब जो प्रश्न उठा है कि उन लोगों को जो २०० के करीब लोग हैं जिनके ऊपर कार्यवाही की गई है उनको फिर काम पर वापस ले लिया जाये तो इस पर सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इन २०० आदमियों को बाहर रखकर क्या परिणाम होगा। यह न समझें कि ये २०० आदमी चुप बैठेंगे। आप नोग जो सरकारी कर्मचारियों का भला चाहते हैं और उन कर्मचारियों को इन आदमियों से दूर रखना चाहते हैं, तो वह आपकी नहीं सुनेंगे। ये दो सौ आदमी आपके लिये ज्यादा खतरनाक साबित होंगे और ज्यादा बलवा ये ही करेंगे। आपके खुद के दृष्टिकोण से भी भलाई इसी में है कि आप इन २०० आदमियों को वापस नौकरी पर ले लें; क्योंकि जो कामकाज करता रहता है अगर वह कोई राजनैतिक काम करे तो कितना कर पायेगा और जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है वह कितना कर पायेगा, उसमें बहुत भारी अन्तर है। जो बिल्कुल खाली है वह ज्यादा करेगा। और अगर आप यह सोचें कि दो सौ आदमियों को निकाल दिया, इसलिये सरकारी कर्मचारी अब सैटि-

[श्री एम० गौरे]

स्फाइड हैं, उनके बीच में कोई संगठन नहीं हो पायेगा, यह एक बचकाना तौर से सोचने का ढंग है। आखिर ये २०० आदमी सरकारी कर्मचारियों के बीच में कुछ मान्यता रखते हैं। यह नहीं है कि वे आज उनका साथ छोड़ दिये हैं। इसलिये अगर आप उनमें बिटरनेस ज्यादा पैदा करते हैं तो यह आगे के लिये आपके हित में खतरनाक साबित होगा। इसलिये मैं भी यह प्रस्ताव जो हमारे सामने रखा गया है, इससे बिल्कुल सहमत हूँ और चाहूंगा कि इसको इस सदन में पास किया जाये और जो संशोधन रखा गया है उसको भी इसमें जोड़ लिया जाये। मैं तो चाहूंगा कि इतना ही संशोधन काफी नहीं है, बल्कि जो सर्विस अब तक उनकी खत्म हो गई है उसको भी उनकी सर्विस में जोड़ दिया जाये . . .

श्री अर्जुन अरोड़ा : थोड़ा इनाम भी दे दीजियेगा उनको।

श्री एम० गौरे : मैं इसका कारण बताऊंगा कि . . .

श्री बिमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : इनाम तो १९४२ के बाद लोगों को मिल चुके हैं, दो बेलों की जोड़ी।

श्री एम० गौरे : जो कर्मचारी आपके सरकारी काम कर रहे हैं उनको कितना इनाम आपने दिया है वह तो साफ है। जो कुछ अत्याचार आपने उनके ऊपर किया वही काफी इनाम मिल चुका है। लेकिन अब कम से कम उनके बारे में ठंडे दिल से सोचना चाहिये और उनको फिर वापस लेना चाहिये और न सिर्फ वापस लेना चाहिये बल्कि जो सारा वेज स्ट्रक्चर है उसको भी आप एग्जामिन कीजिये। हो सके तो देश में जो दामों की लूट हो रही है उसमें और आमदनी में कोई न कोई एक सम्बन्ध रहना चाहिये। जब तक यह सम्बन्ध नहीं होता है तब तक हिन्दुस्तान

में हड़तालें होती रहेंगी और अगर आप उनको बलवा समझें तो ग्लव भी होते रहेंगे। इसलिये मैं तो यह चाहूंगा कि न सिर्फ वेज स्ट्रक्चर बल्कि जो देश में प्राइस स्ट्रक्चर है, उन दोनों के बारे में एक कमेटी बना कर दोनों का एक संतुलन करें और दोनों को एक समान जोड़ें। यह न कहें कि हम तो डियरनेस एलाउन्स दे रहे हैं। डियरनेस एलाउन्स आप दे रहे हैं लेकिन डियरनेस एलाउन्स का मतलब क्या होता है? जब कि दामों की लूट हो रही है तब डियरनेस एलाउन्स का कोई अर्थ नहीं रहता है और इसलिये हमें दामों में संतुलन करना है। मैं सरकार से अजं करूंगा कि दामों का और डियरनेस एलाउन्स का सम्बन्ध कायम करने के लिये अभी से कोई कमेटी बैठा कर उसका कोई प्रबन्ध करे। और यह दलील देना कि बाहर के देशों में हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, उनके वेतन में तो हमने ज्यादा वृद्धि कर दी है, ये सब बातें कोई मतलब नहीं रखती हैं क्योंकि अगर आप बाहर के देशों का भी उदाहरण लेंगे तो बाहर के देशों की स्टैण्डर्ड ग्रॉफ लिविंग में और उनके वेतन में क्या सम्बन्ध है, और उसकी कितनी रीयल इन्कम है और उस रीयल इन्कम से उनको कितना फायदा होता है, इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। यह तो आप देखते नहीं हैं, बस कहते हैं कि हमने तो वृद्धि कर दी है। दस साल में क्या ऐसी वृद्धि कर दी है? वृद्धि तो जो हुई है वह तो एक दस वाटन से हुई है, जिससे कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को पूरा पूरा एग्जामिन करके जब तक सरकारी कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों के वेज स्ट्रक्चर का सही निर्धारण नहीं होता तब तक देश में कोई हड़ताल बन्द नहीं होगी।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को बतलाया गया है कि आप राजनीति में हिस्सा न लें। यह बात

संविधान के बिल्कुल खिलाफ है और इससे फण्डामेंटल प्रिंसिपल्स की अवहेलना होती है। सरकार को इस तरह की नीति जारी नहीं रखनी चाहिये।

श्री अर्जुन अरोड़ा : माननीय सदस्य संविधान को नहीं मानते हैं।

श्री एम० गौरे : मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो संविधान बनाया गया है, उसे एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। जो संविधान फ्रेम हुआ है वह कांस्टीट्यूटिण असेम्बली द्वारा बनाया गया है जो कि एक गुलाम देश की असेम्बली के प्रतिनिधियों की सभा थी। इस संविधान को अभी तक एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। मैंने पिछले दफा भी यही सलाह दी थी कि रिफ्रेंडम कराके जनता द्वारा इस कांस्टीट्यूशन को मान्यता प्रदान करा ली जानी चाहिये। अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और...

श्री अर्जुन अरोड़ा : आपकी सलाह बेसकीमती है मगर उसी संविधान के अन्तर्गत आप यहां पर बैठे हैं।

श्री एम० गौरे : आप यह चाहते हैं कि आपके लिये यहां आने का रास्ता खुला रहे और आप अत्याचार करते रहें। आपके दुर्भाग्यवश हमारी जैसी पार्टियां ऐसी हैं जो इस कांस्टीट्यूशन के बावजूद भी यहां पहुंची हैं।

श्री अर्जुन अरोड़ा : कुछ लोग अपने सूबे में स्थान न पा करके दूसरे सूबों से कुछ गलत तरीके अपना कर आते हैं।

श्री एम० गौरे : उनमें आपकी पार्टी भी है। जो देश की एकता को मानती है।

पार्टी के नुमायन्दे का इस तरह की बात कहना पार्टी के दिमाग का नमूना पेश करना है जो पार्टी नेशनल इंटिग्रेशन की बात करती है जो देश की एकता की बात करती है, उस

पार्टी के एक सदस्य द्वारा यह कहना कि अमुक आदमी उस प्रदेश से चुन कर आया है, शोभा नहीं देता है। मैं आपको यहां पर कई मिसाल पेश कर सकता हूँ कि कांग्रेस के बहुत से मेम्बर दूसरे प्रदेश से चुन कर यहां और लोकसभा में आये हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को जनता ने अपने वोटों से हरा दिया उन लोगों को भी अप्रत्यक्ष रूप से यहां भेजा गया है। इस तरह का पाप कम से कम हमारी पार्टी ने नहीं किया है। जनता ने जिन्हें एक बार ठुकरा दिया है वे लोग यहां पर आये हैं।

तो मैं यह कह रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें यह अधिकार होना चाहिये कि वे राजनीतिक पार्टियों में हिस्सा लें। यह ठीक है कि वे लोग सक्रिय हिस्सा न लें लेकिन सदस्य बनने का उन्हें मौका मिलना चाहिये और इससे किसी को रोका नहीं...

श्री दयाल दास कुर : अगर माननीय सदस्य प्रचार न करें तो अच्छा होगा।

श्री एम० गौरे : हर जगह यह प्रचार करेंगे।

श्री दयाल दास कुरे : तो यहां आने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : यहां आपको समझाने के लिये आये हैं।

श्री एम० गौरे : कांग्रेस पार्टी वाले किसी की कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी तानाशाही देश में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी कि सरकारी कर्मचारियों को या किन्हीं और लोगों को इस तरह का हक न मिले। कम से कम राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का हक सबको मिलना चाहिये। अगर आप यह कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का हक नहीं मिलना चाहिये तो फिर इसका

[श्री एम० गोरे]

मतलब यह होगा कि प्रायः सजाज्जवादी ढाँचे की जो इतनी लम्बी चोड़ी बातें करते हैं वह सिर्फ एक नारा ही है। इस तरह से आप सरकारी फॅक्टरियों और कम्पनियों में जो लोग काम करते हैं उन्हें इस तरह हक नहीं देंगे और चन्द लोग बैठ कर देश का शासन चलायेंगे। इसलिये यह जरूरी है कि आप सरकारी कर्मचारियों पर जो रोक लगा रहे हैं उसे रद्द कर दें।

SHRI P. N. SAPRU: Mr. Vice-Chairman, there is a wide ocean which divides me, so far as the ideology is concerned, from my friend, Mr. A. B. Vajpayee. Yet it is a principle with me never to judge a question from anything but the point of view of merit, of merit of the issue involved. I have therefore applied my mind to the question whether Mr. Atal Behari Vajpayee, who has come forward here as the champion of the oppressed Government servants, has applied his mind to the real problem which has been raised by the Resolution which he has put before us. I have, for this reason, looked into the terms of his Resolution, and I find that they are written somewhat in the manner of a Rip Van Winkle. He assumes that the Government servants against whom action had to be taken were men of a very very innocent type and that really very harsh action has been taken by Government and the Party, which has no element of fairness about it. I will just read out the language of this Resolution:

"This House is of opinion that all the Central Government employees"—*whoever they may be whatever may be their fault—*"who lost their jobs"

Now the word 'lost' is somewhat significant, because it suggests that they were not responsible in the slightest degree for losing their jobs for participation in the Central Government Employees' strike.

"-----for participation in the Central Government Employees' strike
♦♦♦♦♦ be reinstated."

There is not a word of disapproval in this Resolution, in the form in which this Resolution has been placed before us, against those Government servants who under, I think, rather immature leadership of certain political parties went on a strike, and had therefore to suffer the consequences of that strike. Two of the most prominent members of the labour movement—they were greatly interested in the labour movement—the late Mr. Feroze Gandhi and Mr. Khadilkar, almost were on the point of bringing about a settlement of the issue between the employees^{and} employers, the latter being the Central Government here, but yet the employees were so ill advised by men, who should have known better, by men whom experience of life will teach them to be better labour leaders, that they rejected the advice of Mr. Feroze Gandhi and Mr. Khadilkar.

Now I do not wish to enter into the question whether Government servants should have the right to strike or should not have the right to strike at all. The question of this strike or of a general strike raises some very difficult questions of political philosophy, and I must confess that my approach to that matter is not exactly the same as that of Mr. Santhanam who, at all events, for some years, in some capacity or other, has been a bureaucrat.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI AKBAR ALI KHAN: There are High Court judgments that the Government servants' strike was not proper.

SHRI P. N. SAPRU: Speaking quite seriously from the point of political philosophy, from the point of jurisprudence, the question of a strike or a general strike poses very difficult problems and I do not deliberately wish to go into them. If you want to have an inkling into my mind, I may tell you that I have a somewhat sympathetic attitude so far as my concept of socialism is concerned, and there-

fore it is difficult for me to speak on this question with absolute frankness. I would like, therefore, to confine my attention to the question whether the Central employees, who went on strike, have been given a fair deal or not by the Government of the day, and I have deliberately come to the conclusion that they have been given a fair deal, that Government cannot be accused of having acted against them vindictively.

There were about two million Government servants and nearly one-third of them took the decision that there should be a strike. Agreeing to that many of them went actually on strike, after that, the strike was broken up because it was ill-conceived. It was broken up because there was no public sympathy with the strikers. There are certain conditions which must be fulfilled before a strike can succeed. Those conditions were impossible of fulfilment and the strike was broken up and action was taken against a fairly large number of persons. I think, first, about 27,098 persons were suspended. Then, 2,084 persons were dismissed or removed from service. There is difference between dismissal and removal, as we all know. The number of temporary persons discharged from service was 2,137; 11 persons were compulsorily retired and against 45,945 persons departmental proceedings were taken in July 1960.

Now, what is the position in March 1962? The position today is that there are about 208 persons against whom proceedings have not been dropped as yet. The number under suspension today is 15. The number of persons dismissed or removed from service is 136. The number of persons compulsorily retired is 11. The number of persons temporarily tried and discharged from service today is 61, and departmental proceedings are pending against 17, and they continue to be pending against these 17 persons because, I believe, there are writ applications pending before High Courts on behalf of these persons.

Now, Sir, these figures do not show that the Government has been vindictive in the manner in which it has approached this task. The strike was on a gigantic scale. If it had succeeded it would have paralysed the whole life of the community. It would have affected the trade of the country. It would have affected the traffic of the country, and it would have, in fact, almost torpedoed the Five Year Plans in which we are engaged. Therefore, it was a serious decision for these misguided men to go on strike, and yet the Government has acted towards them with that understanding, with that humanity which is expected of a government which swears by certain radical principles. I would, therefore, say that the charge that Mr. Vajpayee, who will have no hesitation in imposing his brand of culture upon this entire country, has brought against us is without foundation.

Sir, this does not mean that I would not like the cases of even these 208 men to be viewed or to be reviewed with sympathy by the Government. Two years have elapsed since the thing occurred. These men must have grown wiser as a result of the experience of these two years and, therefore, as situations change decisions must also change.

May I also say, Mr. Vice-Chairman, that while I am no admirer of the bureaucracy that administers our country, I do not believe in running it down day in and day out. I know their defects and I know their virtues also. Most of the men who are working in superior positions in our Railways or in our post offices are men of integrity and humanity and fairness, and I think that it is incorrect on our part to say that they have not approached these cases in the manner indicated by the Home Minister in his utterance in this House on the question of this strike. I think that they have endeavoured to do their very best to see that justice is tempered with mercy in dealing with the cases of these persons. Therefore, Mr. Vice.

[Shri P. N. Sapru.]

Chairman, I would say that without ruling out the possibility of a further revision of the punishment which has been meted out to these men, Mr. Vajpayee has not been able to make out a case for this Resolution.

Finally, I would like also to say that I am not one of those who think that political parties should have nothing to do with trade unions or trade unionism. If that principle were accepted, there would be no British Labour Party.

SHRI ARJUN ARORA: Does the hon. Member know that the Trade Union Congress of Britain does not allow the Labour Party to interfere in its affairs?

SHRI P. N. SAPRU: It is the other way round. I know the relations of the Labour Party with the Trade Union Congress of Britain very well, and I can assure him that I have read almost everything that is worth reading on the Labour Party and its constitution. It is a very complicated constitution. The proposition that I was making was that political parties there do take interest in trade union disputes, that Labour Party is financed .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Your time is up, Mr. Sapru. Please finish.

SHRI P. N. SAPRU: This remark is, of course, only of an incidental character and I am not prepared to blame any political party which has alliances with trade unions, though I may repeat that I have no particular grievance against political parties taking funds from big commercial houses for running their election campaigns.

SHRI A. D. MANI: Mr. Vice-Chairman, I should like to say that I would like to support the Resolution which has been moved by my friend, Shri Vajpayee. Perhaps it is necessary for me to say that I am not one of those

who support the Government servants to go on strike or for that matter, who supported the Government servants' strike last July 1960. As a part of my credentials, I am saying that when the Government servants of Madhya Pradesh went on strike. I was one of those who appealed and persuaded them to withdraw the strike and they said so in a resolution adopted at that time. I hope, therefore, that no Member of this House would be under the impression that I am interested in fomenting trouble for the Government. I do not want to go into a discussion of the constitutional principles raised by my hon. friend, Shri Avinashilingam Chettiar. On the question of the Government servants' right to strike, the opinion is still divided. There is, for example, the Franklin Roosevelt document which says that Governments cannot be an equal negotiating party with the-strikers if they happened to be Government servants. This view has not been accepted by labour parties in many parts of the world.

SHRI AKBAR ALI KHAN: The preponderant opinion is in favour of the fact that the Government servants should not strike.

SHRI A. D. MANI: I do agree that the Government service is on an entirely different footing from service in private industries and that Government servants must forego certain privileges which are due to workers in private industries but I am only mentioning that the final word has not been said on this subject and I know that a large number of people would like constitutional limitations to be placed on the right of Government servants to strike. I may mention here that apart from all these constitutional principles which have been raised, we should like to go into the background of this strike. I have listened to the many speeches made on this side as well as the other but there has been no reference to the background or the events that led to the unfortunate developments which resulted in the strike. I should like to

say with a due sense of responsibility that the Government offered sufficient, grave, provocative reasons for this strike. We cannot divorce the conduct of the Government in an assessment of the responsibility of those who went on strike. The Ministry of Labour has been asking many industries to raise the D. A. It has been the settled policy of the Ministry of Labour to equalise the rise in the D.A. with the rise in the cost of living and on that account, 100 per cent, of the cost of living in the textile industry has been equalised. Similarly, for other industries. Seventy to eighty per cent, of the rise in the cost of living had been neutralised. Furtlier, in our country, we attach much value to what the Government says. We give the benefit of the doubt to the Government that it does not lie. It is a crude expression I use and I am using it because one of the reasons which led to the strike was the adherance of the Government in the Ministry of Labour to the tripartite Indian Labour Conference decision that the minimum wage in India should be Rs. 125. That was solemnly accepted by the Ministry of Labour as the official policy of the Government of India. Later on when it came to a question of implementation...

SHRI ARJUN ARORA: There was no acceptance of the figure of Rs. 125. There was only the acceptance of a certain formula which, according to some people, worked out to Rs. 125.

SHRI A. D. MANI: I want to read out what Mr. Morarji Desai had said on this subject. When the attention of the hon. Finance Minister was drawn to this, he said:

"The Government desire me 'to make it clear that the recommendation of the Labour Conference should not be regarded as decisions of Government and have not been formally ratified by the Central Government." 188 RS—4.

The Minister of Labour was one of the parties to that Conference. He did not dissent from the recommendations and Mr. Morarji Desai does not agree with the interpretation now given by my hon. friend, Mr. Arora. Further he sas;

"They should be regarded"—that is, these recommendations—"as merely the recommendations of the Indian Labour Conference which is tripartite in character. Government have, at no t_me, committed themselves to taking executive action to enforce the recommendations."

SHRI AKJUN ARORA: The hon. Member has tried to mislead the House. There was no acceptance of any ttgure. According to me, that formula works out to a minimum figure of Rs. 139 and not Rs. 125. There was a formula which was accepted, and not the figure of Rs. 125. He has read something from the papers which he has got.

SHRI A. D. MANI: I read what Mr. Morarji Desai had said. Whether it is Rs. 125 or Rs. 139 or Rs. 200 does not matter. It is much more than Rs. 80 sanctioned by the Pay Commission. I remember that at that time a large number of people met me and said that the Government was going back on its recommendations.

SHRI AKBAR ALI KHAN: On a point of order. Mr. Mani has raised a very fundamental question. If a member of the Government, a Minister, partakes in any international conference, is the Government bound by the fact of that participation? No, unless the Government ratines it. If the Government ratifies it, then of course it is binding, otherwise, there are many conferences in which our delegations participate.

(Interruptions.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): What is your exact point of order?

SHRI AKBAR ALI KHAN: This is a constitutional question.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): There is no point of order.

SHRI AKBAR ALI KHAN: I am referring that to you.

SHRI A. D. MANI: Many people who spoilt to me at that time said that the Government had gone back. They went on strike. A large number of people working under an emotional strain do a number of foolish things. They went on strike and quite a large number of them were charge-sheeted and disciplinary action was proposed to be taken. Now I quite concede that in dealing with the majority of the cases, the Government has acted with leniency but in regard to those 208 people who have lost their jobs, I would like to tell the Government that if a private industry were to do this, the Ministry of Labour would come and say: 'Take back everybody who had gone on strike'. The advice is always meant for the private industry and whenever a strike has been settled in a private industry, the Government has advised the strikers to be taken back. Now my hon. friend, Shri Chettiar, spoke about sabotage and I believe my hon. friend, Mr. Santhanam, also spoke about sabotage. I have been at pains to go through these papers from the Parliament Library to find out whether there was one case of proved sabotage against the strikers. There has been no such case at all and I would like the hon. Home Minister to reply to this specific point whether any conviction has been sustained against a person for acts of sabotage. I would like to have that point cleared because I have been trying to go through all these papers but I have not found any. If it is a question of sabotage, it is not covered by my hon. friend's Resolution because the Resolution says:

"in that time no such opinion that all the
Central Government employees who lost
their jobs for participation in the Central
Government employees' strike . . ."

it is only participation, it is not a conviction.
I would like to say further that when 4 P.M.

dealing with this matter, the

Government should understand that unless there is an avenue open to the Central Government employees to represent their point of view, such explosions would occur. There have been Staff Councils at work and on the floor of the House a large volume of statistics, quite impressive statistics, have been furnished, about the number of cases that had been referred to the Staff Councils and so on. All that shows that the Staff Councils are working very well. But, Sir, if the Government is to deal with the economic situation satisfactorily, they should understand that the Government servants are also part of the working population in this country and they should treat the Staff Councils as some sort of a negotiating body. Last year a Member of the British Parliament came to India. Mr. Douglas Houghton, a Labour M.P. came here with the British delegation to the Commonwealth Parliamentary Conference and he met the Prime Minister and had long discussions about Staff Councils and the trends of the Staff Councils of the Government of India. These made a very powerful impression but he said they had these in 1919 in England and not in 1957. I would like to read what he wrote to a Member of Parliament here at that time—Mr. Shiva Rao—who had sent him a copy of the constitution and rules of the Staff Councils. He wrote:

"The interesting enclosure to your letter"—that is to say, the instructions for the constitution of the Staff Councils—"takes me back to the first proposals put forward by

our Government here in 1919, when the Whitley Report came out."

Then he goes on to the constitutional question about the government having the right to decide what the workers should get and so on and says: —

"This, of course, is purely constitutional fustian, unrelated to the fact"

And this relates to the point raised by Mr. Avinashilingam Chettiar,

"unrelated to the fact that in practice it is not the people who fix the pay and conditions of Government employees but Ministers and higher Civil Servants. They already have the power of decision; and there is no reason why they should not reach their decisions in the course of negotiation."

The Government servants wanted negotiations at every stage before going on strike, but the Government was not prepared to accept negotiation. Though it was felt at that time that the hon. Minister of Labour—Shri Nanda—sympathised with them, the Finance Ministry of the Government of India and the Home Ministry took the decision that there was not to be negotiation.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Has that been brought on record?

SHRI A. D. MANI: After all hon. Members on both sides of the House say so many things which are not on record and it is all known to everyone in the House who has dealt with the labour situation in the country. Sir, the way in which public enterprises are expanding, there is grave danger of substantial part of the population losing their fundamental rights by becoming Government servants. There are so many enterprises coming up that by the Fourth or Fifth Plan, about half the population will be in the public sector, and we will lose our fundamental rights. If

the Government had established Staff Councils which had negotiating powers, the present situation would not have arisen.

I should like to take the House to the decisions taken by the Government after the termination or failure of the strike. Virtually the Government met the point of the strikers half-way; but they were not prepared to do so just at that time. Sir, the economic situation is bad in the country. The Railway Minister has proposed a rise in fares, and the Central Budget also has its own quota of taxes. The purchasing power of the rupee is going down. It was the economic distress and misery which made the Government servants go on a strike. It is a very human problem. With regard to those who have lost their jobs, I would like to give my own experience. I will relate from my own experience of what happened in Nagpur. I was in touch with many who took part in this strike and one officer served notice on a person who belonged to a rival cultural society, of which the officer was not the President. There were two societies in Nagpur and he was the president of one society. There was another so-called person who was putting up a very active performance. That person who took part in the work of the cultural society which was in his notice. This is what happened.

SHRI AKBAR ALI KHAN: That was wrong.

SHRI A. D. MANI: That was wrong. That is what I am saying. As the hon. Member, Mr. Sapru, with the judicious wisdom with which he approaches all these questions in this House has said, a large number of people have suffered I believe the Auditor-General's Office has the largest number of such casualties. It is not the Auditor-General who has taken the decision in all these cases. It is the local officers who have got

[Shri A. D. Mani.]

some resentment towards some persons who have taken the decisions. Persons who have put in 32 years of service have been retired, and in Bengal one man committed suicide because there was a suspension order.

AN HON. MEMBER: Yes.

SHRI A. D. MANI: You know that case. I would like to say that the Congress Party, when it came into power in 1937, released murderers from jail. In 1947, after the termination of the Civil Disobedience Movement and after the Congress was asked to form the Government, then also they released persons convicted of criminal offences. I would make an appeal to the hon. the Home Minister. Let bygones be bygones.

AN HON. MEMBER: Which murders, has the hon. Member in mind?

SHRI A. D. MANI: I have got a large number of them and if the hon. Member likes, I can give him a list of those cases which happened in Madhya Pradesh, where so many people were released. I would make One appeal to the Home Minister. The strike is over and the Government servants have got a new frame of mind. Let all these cases be examined with a fresh mind, and not by the departmental officers, but by men of judicial standing like the hon. Member, Mr. Sapru, and let these people get back their jobs. We have come here only on a mission of mercy, with the request that the people who took part in a thoughtless mood in the strike should not be penalised and their families should not starve.

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Mr. Vice-Chairman. I will not take much time of the House, but since the Railways have been mentioned prominently in this debate, I have ventured to intervene. We in the Railways have been very fortunate in having very cordial relations between our workers and the Railway

Administration. As you are aware, we have two Federations, to whom we had given facilities for negotiating with the Railway Board. One is the National Federation of Indian Railway Men and the other is the All-India Railway Men's Federation. Sir, at one time the facility for negotiating with the Railway Board was not available to the All India Railwaymen's Federation. Shri Jagjivan Ram, who was then the Railway Minister and who always has had a very sympathetic outlook and sympathetic behaviour towards all labour problems gave those facilities to the Railwaymen's Federation. At the time this strike came. Sir, all the very important issues which were made the main issues in the strike also were under negotiation and discussion with the Railway Board. The National Federation of Indian Railwaymen had negotiated with the Board and had practically induced the Railway Board to accept most of their demands but when the strike intervened, those decisions had to be delayed. Sir, all I can say is that as far as we in the Railway Ministry are concerned we have always had cordial relationship with our employees and we intend to do everything possible to retain that happy relationship and I can assure you, Sir, that we have no intention of taking up a vindictive attitude or an attitude of revenge against any of our employees.

I have here some figures which I would like to place before the House. Initially, as many as 10,815 employees were suspended and now out of this number only six are still under suspension because their cases are still under investigation or some sort of departmental investigations are going on. Now, coming to dismissals and removals, there were 478 cases of removal out of which all excepting 64 employees have been put back on duty.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): What about the leaders of the movement?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Out of the temporary staff and apprentices, notices for removal were served on 12,325 employees and out of this, only 43 temporary employees or apprentices stand with their services terminated. This is the attitude we have taken.

SHRI M. J. GURUPADASWAMY (Mysore): May I know the reasons on the basis of which suspensions or dismissals have been revoked in these cases? How do they differ from the reasons in respect of the other cases that are still there?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: The main reason why people were removed from service was the use of criminal force against the officials, supervisory staff or against their colleagues preventing them from going to their jobs and so on. Some employees were beaten up and their families were harassed. Those who wanted to go, those loyal workers who wanted to go and keep the trains moving were physically prevented from doing so.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: May I ask whether there has been registration of these cases and whether there has been any case of fine in a court of law?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Yes, Sir, there were several cases of that nature. Cases went to courts and there were convictions by the courts. On the basis of those convictions some of the employees were removed from service.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Mav I know whether in the few cases that are still there, the cases mentioned by the hon. Minister, action either by way of dismissal or suspension has been taken after these cases have been proved in a court of law?

SHPI SHAH NAWAZ KHAN: Not all of them.

SHRI	NIREN	GHOSE:	How
many?			

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: My hon. friend, Shri Mani, said that he had waded through a large number of files and he had not been able to come across a single case of sabotage. I would like to give him some figures. On the Railways, there were eight cases of derailment of trains due to deliberate acts of sabotage and you can imagine, Sir, what might have been the consequences of such acts of derailment of trains. These might have led to serious accidents in which a large number of passengers might have been killed. These are the type of cases in which we have been constrained to take action against them.

SHRI NIREN GHOSE: May I know whether the Railway Board's circular also regards the procedure for charge sheeting and suspension and all that was implemented in practice?

SIRI SHAH NAWAZ KHAN: Sir, there were several cases of cutting of the cables and signals wires, telegraph wires and there were a large number of cases where fire was dropped deliberately. The train was taken and half-way through fire was dropped and the passengers were stranded there. Surely this is not a type of conduct which the hon. Members would like to encourage. In spite of all these things, Sir, as I said in the beginning, we were determined not to take a vindictive attitude and we in the Railway Ministry examined almost every single case of the Railway employees who have not been put back on duty and again I should like to assure the House, Sir, . . .

SHRI A. B. VAJPAYEE: I do not want to intervene but then there are appeals still pending. How can he
I say that every case has been examined?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Whatever case has come to us so far. I again reiterate here that we have no rigid attitude and in case any hon. Member of this House feels that there is room for reviewing in any particular case and if such a case is referred to us, I can assure the hon. House that that case will be examined thoroughly not at the lower level or the level of junior officers but that the case will come up to the highest level, to the Minister. I can assure the House that if there are any cases where hon. Members feel that there is still room for re-examination, in those cases we shall only be too glad to do so.

Now, Sir, some hon. Member opposite said that the damage that had been done was very small. Some said it was Rs. 21 000 and some others said that it was Rs. 30,000. Sir, here are some figures from the Railway Ministry side which I would like to place before the House.

श्री विमल कुमार मन्नालालजी चौरडिया :

यहाँ जो पर लोक सभा में

SHRI SHAH NAWAZ KHAN:
आपने फर्क दिया और मैंने मून लिखा
अब मैं अर्ज करता हूँ और मेरी भी मूज-
रिज मून लीजिये ।

Sir, the damage on account of loss of production came to Rs. 38 29,000. We lost Rs. 3,17,59,000 on account of loss due to reduction in traffic. We were entrusted with the care of public property and we had to make special arrangements and On that account we had to spend Rs. 6,81,000. Damage to Government property accounted for Rs. 24,100. This, Sir, gives a total of Rs. 3,62,93,100—the actual damage done as far as the Railways are concerned. Then one hon. Member said that we should have acted like parents when they are confronted with their disobedient children. Sir, the whole country knows what happened. The strike notice was given: 'Accept our demands or we strike' and under that threat we were asked to start nego-

liations with those who had issued the strike notice. We said, 'we are quite prepared to talk to you; we are prepared to negotiate with you but please do not come and negotiate with us at the point of a pistol. Withdraw the strike notice and then come to us and we are quite prepared to discuss with you', but they were not prepared to do so.

In the end again I wish to emphasise that we have no feeling of revenge or vindictiveness towards our own employees but I would like to request my hon. friends opposite who are so fond of inciting the employees to go on strike on the least pretext that the consequences of misleading the employees can be very serious for those employees. If those employees are in trouble if their children are starving today, if they are in this terrible plight, they have to a great extent thank the gentlemen who misled them and I hope in future they will not follow those gentlemen so easily.

Finally, I would like to say a word in praise of the very large number of patriotic workers who in spite of these efforts by various people to mislead them stuck to their posts of duty and kept the wheels moving. The National Federation of Indian Rail-waymen, that patriotic organisation, stood up to a man and took it as a challenge to the country. Sir, when our beloved Prime Minister said that this was not a mere strike but it was a challenge to the whole country, those patriotic railway employees stood up and showed that in spite of whatever other people might do, they would keep the trains moving and they did. And I would, through this august House, again like to congratulate those employees and to thank them for the very wonderful work that they did during that time. We also owe a great debt of gratitude to the general public who co-operated with us who extended their full sympathies to the Government. As I said, although we have an open mind

and we are always prepared to reexamine the cases, we cannot accept this principle that everybody who took part in the strike—whether they committed assaults on superior officials—should be taken back. That principle, I am afraid, we cannot accept.

SHRI SUDHIR GHOSH: Mr. Vice-Chairman, I have only a very few brief sentences to contribute to this discussion and I wish to do so, particularly because there are certain matters of principle involved in this discussion.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. SUBBA RAO)
in the Chair]

When I interrupted my hon. friend, Mr. Bhupesh Gupta, this morning asking how this sort of a situation was dealt with in the U.S.S.R., he did not seem to like it. Now, Sir, it is the history of Communism all the world over that 'When our Communist friends are in the opposition in a country they are very fond of freedom. Freedom of speech, freedom of the individual civil liberties, parliamentary government, democracy, all these beautiful freedoms they are very fond of but as soon as they come to power they have no use for these beautiful freedoms even for one day. When a man like our friend, Mr. Bhupesh Gupta, makes such a forceful speech on behalf of these sentiments, one feels a little sceptical about it. That does not mean, the fact that I disagree with Mr. Bhupesh Gupta's eloquence does not mean that I accept the position taken by my friend, Mr. Santhanam, as regards the Government officials' right to strike. As soon as you say that no Government employee should have the right to strike, you fall into the trap of Mr. Bhupesh Gupta himself because that is what the Communists claim in their own country. I have been to Russia and I have studied their industrial orga-

nisations and their workers' organisations, 'Inere the Government says to the workers, 'Look here, this industrial unit, this steel plant or any other plant, belongs to you, belongs to the people. How can you strike against yourself? It is absurd. And that is all that they have to say of right to strike in those very free countries. Therefore we have to be very careful when in answer to a person like Mr. Bhupesh Gupta we put forward the argument that we do not believe in any Government employee's right to strike. We are on very dangerous grounds there. In the United Kingdom, for instance, if anybody suggested that a nationalised industry like the coal mines, that is, the coal miners of Great Britain should not have the right to strike, well, he will get short shrift. Why coal miners? Even civil servants; they have their Civil Servants' Unions. Whenever a law of the land permits the union of workers and gives them the right of collective bargaining, we must be very careful not to interfere with those rights. But the issue that is involved here is not whether the Government employees have a right to strike or not. The real issue that is involved here is that here was a situation in India where a Government's very right to govern was challenged. Its very existence was challenged and any Government which is worth the name of a Government cannot but reply to that. Now, I want to make clear one thing. There are Government employees like the Posts and Telegraph employees, Railway employees and as my friend, Mr. Mani, has pointed out there are more and more public sector enterprises coming up but there also we are slightly mistaken because the members of all Government enterprises are not regarded as Government servants. For instance the employees of a steel plant under the Government have just as much right to strike as the employees of the Tata Iron and Steel Co. or the Indian Iron and Steel Co.

SHRI A. D. MANI; They will lose it very soon.

SHRI SUDHIR GHOSH: We must make sure that they do not lose it but that is not the point. The point is whether the Government employees have the right to strike or not. There are well-defined limits within which they are allowed to strike but this was a very different kind of a situation and those who organised this Government employees' strike and the general strike did a very dangerous thing for the life of the nation. They organised the disruption of the communications system—railways and postal communications—and they did not have any control over the forces of disintegration which they let loose. It is all very well to organise a strike. You may have a sense of grievance against the Government and the Government may have failed to give you satisfaction on all counts in this particular dispute; but that is a different matter and there are other ways of meeting that situation than letting loose forces of disruption and disintegration in a country which is already overburdened with many such forces. And that was a very dangerous kind of game to play. Those politicians—never mind the party or the group to which they belong— whoever organised it, did not do an act of service to their own country. It was a very dangerous thing to do. So what I object to is this challenge by some organised groups to a Government's right to govern to a Government's very existence and that has got to be met very forcefully and the Government did right in taking stern and decisive action. Of course in fairness it must be said that before the Government took that action, even in the initial stages of negotiations in this dispute it may be claimed that perhaps the Government could have been more prompt in dealing with those problems and perhaps more expeditious action could have been taken in time to avoid all the bitter-

ness. But that is different from saying that Government did not do what it was expected to under the laws of the land. They did all that was required of them in the circumstances and in the end the Prime Minister himself made an appeal to them, not as a party leader but as a national leader, pointing out . . .

AN HON. MEMBER: The Prime Minister did not meet them.

SHRI SUDHIR GHOSH: Well, he did certainly make a broadcast appeal as far as I remember. He did not deal with it on the party plane but on a higher plane, as a dispute between the employer and the employees. I for one was rather touched by that appeal. Now, who are the people who suffered as a result of this strike? It seems quite clear that it was not the primary consideration of those who organised the strike to secure for the strikers their rights; perhaps they were motivated by a desire to improve their own political position, either as individuals or as groups. That maybe an uncharitable suggestion but that was the impression in the country and it was not the Government, it was the people of the country who rejected this strike. I was in Calcutta at that time. Calcutta is a city full of troubles. I remember how people were buying their household goods, their foodstuffs and vegetables for weeks and weeks, because they thought that some-dreadful things were going to happen in this country. Fortunately it was saved in time and the economic life of the country was not very seriously dislocated. Therefore, we must be quite clear in our arguments here that it is not the right of certain classes of Government employees to strike in a certain situation that is in question. We are not questioning it.

We are questioning the right of any organised group to challenge the existence of the Government. I do not accept that position.

SHRI NIREN GHOSH; That was not questioned at all.

SHRI SUDHIR GHOSH: Now, if it is a question of giving consideration to 200 odd people, who seem to have lost their jobs, that is another matter. We could deal with it on a different plane. We know what sort of man the Home Minister is. I believe, it does not matter whether the man belongs to the Government side or any particular group in the Opposition in this House, everybody in this House has a special kind of feeling for the Home Minister, a feeling that he is a man with very great integrity of mind, a man of great humility. Now, I think it is better

SHRI A. D. MANI: May I ask the hon. Member whether he would like the Home Minister to review the cases himself or allow them to be reviewed by persons of judicial standing?

SHRI SUDHIR GHOSH: All I was going to say is this. We have discussed the question threadbare. We know the whole history of this issue. Now, in the end we are saying that there are 200 odd employees who have suffered. Now, I do not want to go into the merits of these cases. All that I would care to say is that if the Home Minister says to us that he is prepared to look into these cases and wherever possible he will treat them with mercy—because justice also should be tempered with mercy as the hon. Member, Mr. Sapru, said—and do whatever is possible, well, I for one am more than satisfied.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, it is always a pleasure to listen to the lucid and forceful speech of my friend, Shri Atal Bihari Vajpayee, who has moved the Resolution which is being discussed by this House today. Probably it seems Mr. Vajpayee is not aware of all the facts of the case and how the strike came about and he has taken up this CM* because of sentimental reasons. I will show presently how political motives were there for the strike and

188 RS—5.

how it was prompted by interested parties.

Now, let us examine what the condition was immediately after the Pay Commission's recommendations were presented in August 1959. Immediately after the Pay Commission's Report was presented and more particularly after Government's orders were issued in the last week of December extending the working hours on Saturdays and curtailing, to some extent, casual leave and public holidays, the various all-India organisations of certain sections of Central Government employees, chiefly the All India Railwaymen's Federation, the National Federation of Posts and Telegraphs Employees, the All India Defence Employees' Federation and the Federation of Central Government Employees, built up a tempo of agitation for discounting the favourable recommendations of the Pay Commission accepted by the Government, and highlighting the few unfavourable recommendations implemented by the Government. A convention held in Bangalore under the influence of the Communist Party of India in December, 1959, appointed a Joint Council of Action to negotiate a satisfactory settlement with the Government by 15th May, 1960, and failing that to organise a general strike. This was in December 1959.

I had the privilege of moving a motion in this House on the 17th February, 1960, which reads as follows:—

"That the Report of the Pay Commission 1957-59, and Government's decisions thereon, laid on the Table of the Rajya Sabha on the 30th November, 1959, be taken into consideration." This was the motion before the House and I would like to invite the attention of the House to the amendments tabled to my motion by the Communist Party in this very House. There were four amendments, namely:—

1. "and having considered the same this House is of the opinion

[Shri M. P. Bhargava]

that Government immediately restore the cut in holidays and leave facilities enjoyed by the Central Government employees and convene a conference of the representatives of their organisations for a bipartite settlement of the disputes arising out of these recommendations."

2. "and having considered the same this House rejects the wage and dietetic norms suggested by the Pay Commission and holds that all wage-fixing authorities abide by the recommendations of the 1957 Indian Labour Conference."

3. "and having considered the same this House regrets the attitude of the Ministry of Finance in playing down the recommendations of the 15th Indian Labour Conference and holds that Government should stick to and abide by those recommendations."

and

4. "and having considered the same this House is of the opinion that in view of the rising trend in prices the Dearness Allowance in all Central Government Departments and establishments be linked with the cost of living index in accordance with the recommendations of the Varadachariar Commission."

That is the First Pay Commission.

Now, during the course of the debate some sort of threat was given by the Communist Party through its representative, Dr. Raj Bahadur Gour, who was speaking on my motion. This is what he said: —

"Well, of course, I am threatening you on behalf of the employees and we will not allow you to do it, we will fight and we will fight a hard battle to see that the gains are retained; you have no right to tamper with these gains".

This is what happened in this august House.

Now, I will read out to you the charter of demands by the strikers, as given by the Joint Council. Their first demand was grant of a national minimum wage in the light of principles enunciated by the 15th Indian Labour Conference and the determination of suitable differences between the lowest paid and the higher class of employees. Their demand No. 2 was for dearness allowance on the basis of cost of living index on the basis of the First Pay Commission Report. Their third demand was for the appointment of Standing Boards for settling disputes relating to scales of pay and other service conditions. The fourth demand was no curtailment of existing amenities, rights and privileges. The fifth demand was reference to arbitration of disputes referred by either party and recognition of one union in one industry by determination of the representative character of the union through referendum held bi-annually. Their last demand was withdrawal of rule 148 of the Railway Code and the proviso to rule 1709 about the powers of General Managers to discharge an employee after giving due notice.

Now, Sir, if you compare the amendments moved in this House and the first of the four demands made by the Joint Council, you will find that in substance they are the same. They are the same exactly. My friend, Mr. Bhupesh Gupta, was pleased to say that the strike was spontaneous, that it was not pre-planned. Well, I beg to differ from him and would say that the position as indicated by the chronological events is not like that. They were trying outside for bringing about an agitation. They tried to press their demands in this august House, and probably in the other House—I am not sure of it—and all the demands were negatived. When the demands were negatived in this House, what did they do? They again went out and made their plans. The Joint Council launched large-scale preparations in June 1960 to collect funds for a general strike and to build up mass support for a strike call. They gave the strike call, and what was the response?

There are more than 19 lakhs of civilian Central Government employees. They could not get response in spite of all their publicity, in spite of all their preparations, from more than one-third of the employees. That was the state of affairs. When they gave notice of a strike, there were negotiations being held between the Joint Council and the representatives of the Government. My friend, Shri A. B. Vajpayee, had made a reference to my dear friend who is no more, Mr. Feroze Gandhi, and to the part played by him in seeing that the strike did not come off. But he failed, not because the Government was not prepared to listen to them, not because there was any lack of sympathy from the Government for their legitimate demands, but because the attitude of the strikers was very rigid, and they had very great plans for paralysing the life of the country. Some of them even thought that this might provide them with a handle for usurping or taking away the power from the Government which was in existence at that time. And if really they had succeeded in their plans, the country would have been faced with a very critical situation, and it would have meant chaos in the country. Fortunately they did not.

Now I was talking about negotiations and the rigid attitude taken up by them. The hon. Prime Minister on the 7th July, after the negotiations had failed, in a broadcast message made a fervent appeal to Government employees against going on strike and assured them that the Government were prepared to give favourable consideration to any of the Pay Commission's recommendations involving financial consequences and that there should be a proper method for the implementation of the decisions made and that arrangements should be made for joint consultations and negotiations between representatives of the Government and of the employees in regard to implementation. The Joint Council of Action, however, rejected

the Prime Minister's plea for a reconsideration of the strike decision. And then the strike call came, and the strike could not be continued for more than a day.

Members have said from the opposite side that there was no loss, that there was nothing, that the loss was Rs. 21,000, and so on. They forget the colossal loss which the country has suffered by that strike. My friend, Shri Shah Nawaz Khan, has given figures about the loss sustained by the Railways which came to about Rs. 3½ crores and, as I am told, the other Ministries of the Government had to incur an expenditure to the tune of Rs. 4½ crores for making emergency arrangements to meet the situation—Rs. 4½ crores by the Government of India and Rs. 3½ crores by the Railways; that makes a total of Rs. 8 crores. My friends will forgive me if I say that the loss caused by the strike is not to the tune of a few thousands of rupees but is to the tune of Rs. 8 crores. And Rs. 8 crores is no joke. Besides this, the harm done by the strike to the progress of the Plan is hard to calculate. So, the loss, if I may put it, is not in any way less than Rs. 10 crores or so.

If my friends opposite had not instigated the workers to strike and if they had not compelled them to give the strike notice, probably all this country's money could have been saved and utilised in better ways. But whatever was to happen had happened, and now my friend, Mr. A. B. Vajpayee, has come before this House with the present Resolution. If Shri Vajpayee had pleaded with the various Government Departments for consideration of individual cases where he felt that any injustice had been done, it would have been a better course and probably he would have had a better ear from the Government in that case and probably he would have got the support of this side of the House also in getting redress in those individual cases where really hardship had been caused. But he has adopted the other course of

Govt. Employees

[Shri M. P. Bhargava.] bringing in this Resolution. Now if this Resolution is accepted, what will it mean? It will mean that you give encouragement to indiscipline, that you give indirect encouragement to violence, that you do not care for the country's money; let people do what they like, let them act in whatever manner they want, and then somebody or other will act as an advocate for them in this august House.

I am sorry that a seasoned parliamentarian like Shri Atal Behari Vajpayee has chosen this course of bringing in this Resolution before this House which will do more harm to the cause which he wants to plead.

SHRI P. K. KUMARAN (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Resolution before us is a very simple one. The issue involved is the reinstatement of 208 employees who have been victimised. But in the course of the discussion, a lot of political heat was sought to be created and I am afraid that if that is the light taken, the discussion will only do harm to the employees concerned.

The Central Government employees' strike is recent history and I am sorry to see that certain facts have been distorted. It is a fact that when the Council met in Bombay, its first decision was to negotiate with the Government. It was only when the Government refused to negotiate with them that they gave the call for taking the strike ballot. Even after that, their attempt to start negotiations was refused by the Government. It is a fact. Actually what happened was a series of interviews with the Ministers, and the Ministers had always been saying, you call off the strike notice, do this or do that and only then would the negotiations take place. Anyway, out of the 208 employees now remaining to be taken back, 113 belong to tire Railways. I welcome the statement of the hon. Minister that they are prepared to consider their cases leniently. It is not denied that the Government was lenient. But the cases involved, the

in the strike

remaining cases, are not, as the Minister says, cases in which violent actions have been involved. I take the cases of six employees who are still to be reinstated on the Southern Railway. Only five remain now. One man, Mohan Naidu, a striker from the Perambur Workshops died four months back. A man with a large family, he died of starvation. Another man, Narayanaswamy from Bangalore, was charged with assault on a driver. "He was acquitted by the court but he is not yet taken back. Two others were Anglo-Indians. They were not members of any trade union. They were simply drawn into the struggle because of the justness of the cause. I do not know for what reason they have been removed from service. Like this, many of the people who are now remaining are not active trade union organisers or active trade unionists at all. Hence, I appeal to the Government to review their cases once and for all instead of waiting for individual representation; I appeal to them to review the cases of all the 208 people completely and do justice to these employees because it is a question of living. One hon. Member was asking: was it difficult for these 208 employees to And employment? The question here is that these men have been in service for the last ten, fifteen or twenty years and at this late stage, it is very difficult for them to seek employment elsewhere and to start a new life. I therefore support the Resolution moved by Shri Atal Behari Vajpayee and also the amendment. The administration in the Secunderabad Division of the Central Railway was very cruel in this affair. There are nearly 22 employees who are yet to be reinstated. In Secunderabad a 'C' grade driver was reverted to a 'C' grade fireman's post and transferred to Jhansi. Such unmerited reversions are there; a number of reversions are there. So, I appeal to the Government to reconsider the cases of all these employees and issue order, for reinstating them as a May Day gift to the Central Government employees'

organisations. Such a gesture of goodwill will help develop good relations between the Government and their employees.s

SHRI ARJUN ARORA: Mr. Vice-Chairman, the Resolution and the speeches made in its support will undoubtedly make the Government servants, particularly those out of employment—thanks to the strike—say this evening, 'God, save us from our friends. We will look after our enemies.' The Resolution and the speeches have shown the utter ignorance of most of the speakers of the problem? that were involved in the strike. The speeches have also shown that at least some of those who supported this Resolution were out to make political capital out of the misery of the Government servants. I am a humble trade unionist who can claim to have devoted the whole of his lifetime in the service of the working class, Government servants not excluded. And I would be most happy if all the persons who lost their jobs are reinstated. But I am opposed to—and every good trade unionist will be opposed to—the attitude which the mover of the Resolution amply demonstrated in his speech. Shri Bhupesh Gupta had to admit that the Government gave an assurance that leniency would be the guiding policy in its treatment of the employees. Shri Bhupesh Gupta, his thunder apart, his practice of trying to convert this House into an Ochter-lony Maidan meeting apart, had to admit that the Government had adopted a lenient attitude, and I am sure he knows that the Government will continue to adopt a lenient attitude in individual cases in spite of what has been said today.

Sir, a few facts concerning the strike may be narrated with advantage, particularly for the education of the Mover and some of his supporters. It was not the case—as Shri Vimalkumar Chordia, the new enthusiast, take a new Mussalman eating onion?, too much, tries to make out—that the Government did not accept the Pay Commission's Award. It has been pointed out repeatedly that as early as November, 1959, the Government accepted the main recommendations of the Second Pay Commission and on points on which there was no decision in November, 1959, the Prime Minister, before the strike began, gave a solemn assurance that the recommendations of the Pay Commission would be heeded as an Award. Subsequent events have shown that the Government has respected that undertaking. The Government has carried it out and recently the dearness allowance of Government employees has been increased with effect from November, 1961. It was dearness allowance which was in dispute and . . .

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. SUBBARAO) : You can continue the next day.

SHRI ARJUN ARORA: Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A. SUBBARAO) : Further discussions on this Resolution will stand till the next Private Members' Resolutions day.

The House stands adjourned till 11-00 A.M. on Monday, the 30th April.

The House then idjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 30th April 1962.